रोहतक
रविवार, 30 नवंबर, 2025
मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष
दशमी वर्ष : 29, अंक : 301
पृष्ठ 14 मूल्य 3 .00

मौसम
अधि. 26.5
न्यून. 7.8

हरिभूमि

हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित
समाचार ही नहीं, विचार भी
haribhoomi.com

05 आज से भारत-द.अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज, रोहित और कोहली की कड़ी परीक्षा

दीन दयाल जन आवास योजना

Payment Plan 10:40:25:25

दीन दयाल प्लॉट हरियाणा

UNDER DEEN DAYAL JAN AWAS YOJNA 2016, GOVERNMENT OF HARYANA

RERA REGISTERED

फ्री होल्ड आवासीय प्लॉट

सेक्टर-12ए, झज्जर, हरियाणा

General Public is hereby informed that Affordable plots under Deen Dayal Jan Awas Yojna is open for Registration

CC & OC Applied - Ready to Registry

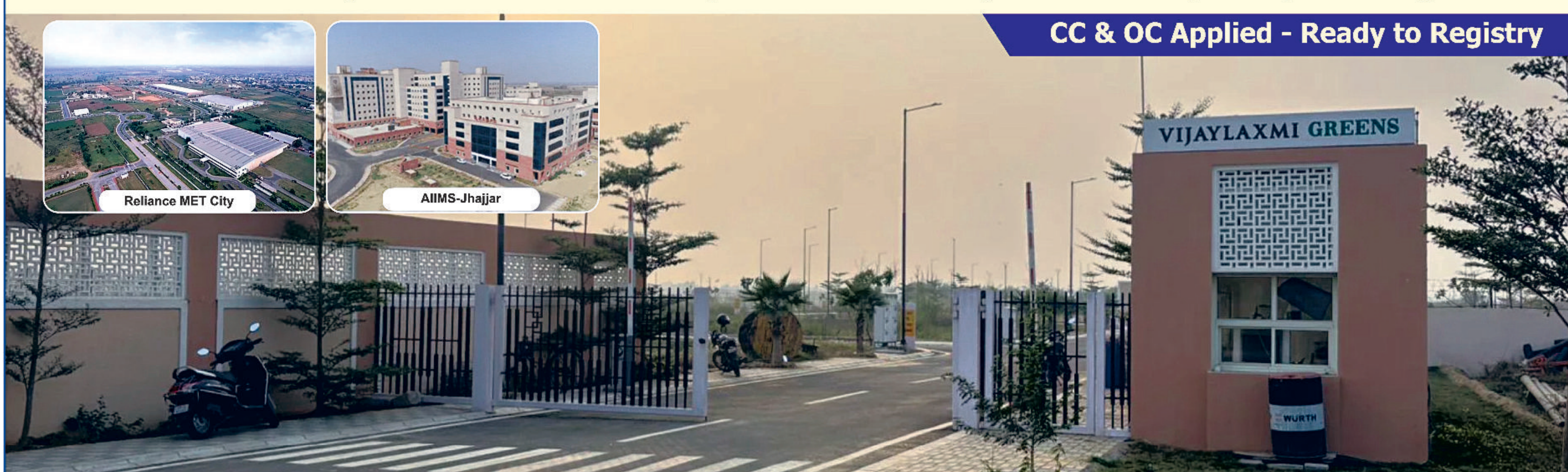

केवल 50 प्लॉट के लिए आवंटन आमंत्रण

LOAN AVAILABLE FROM - SBI punjab national bank

33% महिलाओं एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित

हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत दीन दयाल आवास योजना में अपना प्लाट

Pay Just Rs. 31,000/- for Registration

(Registration Amount refundable to all unsuccessful applicants)

Last Date of Registration: 07th December, 2025 | **Allocation Date: 10th December, 2025**

PAYMENT PLAN

S.No.	Area in (Sq. Yd.)	Area in (Sq. Mtr.)	Registration Amount	10% Payment within 5 days	40% Payment within 30 Days	25% Payment within 90 Days	25% Payment on Offer of Possession	Total Cost
1	138.06	115.42	₹ 31,000	₹ 6,06,083	₹ 24,24,334	₹ 15,15,209	₹ 15,15,209	₹ 60,60,834
2	151.68	126.80	₹ 31,000	₹ 6,65,875	₹ 26,63,501	₹ 16,64,688	₹ 16,64,688	₹ 66,58,752
3	152.90	127.82	₹ 31,000	₹ 6,71,231	₹ 26,84,924	₹ 16,78,078	₹ 16,78,078	₹ 67,12,310
4	154.91	129.50	₹ 31,000	₹ 6,80,055	₹ 27,20,220	₹ 17,00,137	₹ 17,00,137	₹ 68,00,549

Taxes & other charges as applicable*

RERA REGISTRATION NO.: HRERA-PKL-JJR-545-2024 (VIJAYLAXMI GREENS-III)

PROJECT AMENITIES

Attached Market

Kids' Play Areas

CCTV Camera

24x7 Security

Open Gym

Location Advantage

- Bus Stand 500 mtr
- Railway station 1.5 km
- Reliance MET city 10 minutes
- AIIMS hospital jhajjar 15 minutes
- Dwarka Expressway 25 minutes
- Rohtak Rewari Highway 1.km

For Online Registration: www.deendayalplotharyana.org

HELP LINE: +91-85953 34400

Scan with Google Lens & Register

Disclaimer: The Project is registered under the name "Vijaylaxmi Greens-III" with HRERA No.(HRERA-PKL-JJR-545-2024) VIJAYLAXMI INFRABUILD PVT. LTD. Ltd. is the promoter and developer executing the Project. Registration Amount is refer as the E.O.I Amount which is refundable in case of non allotment.By using or accessing the brochure/ advertisement, you agree with the disclaimer without any qualification or limitation. All the images, walkthroughs, and rendered images used in this advertisement are only artistic impressions and are merely indicative in nature, which may or may not vary from the actual designs. The information in this advertisement is presented as general information, and no representation or warranty is expressly or impliedly given as to its accuracy, completeness, or correctness. It does not constitute part of a legal offer or contract. The user must verify all the details and specifications, including but not limited to area, amenities, specifications, services, etc., individually. Notwithstanding anything, in no event shall the company, its directors/partners, employees, or agents be liable to the user for any damages, losses, causes of action, errors, or injury, whether proximate or remote, direct or indirect, consequential or incidental, suffered or incurred by any person(s) due to any use of and/or inability to use this information. Journey time shown, if any, is subject to traffic and road conditions at the relevant point of time. The rate mentioned is exclusive of GST and statutory charges (if any). T&C apply. 1 sq.yrd.=0.836 sq.mtr.

खबर संक्षेप

स्वदेशी अपनाने से देश मजबूत बनेगा : नागर

चंडीगढ़। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वर्ष 2047 तक भारत आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर नागरिक का स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अभियान के तहत बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों से भारतीय उत्पाद खरीदने की अपील की।

गीता का धर्म एवं दर्शन पर गहरा प्रभाव : विपुल

चंडीगढ़। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने रेवाड़ी बाल भवन में आयोजित जिला स्तरीय गीता महोत्सव का अवलोकन किया। राजस्व मंत्री ने कहा कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि उत्तम जीवन जीने का सिद्धांत है, जिसमें जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान मिलता है। श्रीमद्भागवत गीता ने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया है। इसलिए हर व्यक्ति को गीता के संदेशों को अपने जीवन में अपनाकर बेहतर समाज निर्माण में योगदान देना चाहिए। गीता हमें कर्म की शिक्षा देती है और इसका सार समान रूप से प्रासंगिक है।

भगवद्गीता मानवता का सर्वकालिक ज्ञान : शर्मा

चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने सोनीपत में जिला स्तरीय गीता महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर कहा कि भगवद्गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान, कर्तव्य का सार और संकट में साहस का आधार है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य उपदेश आज भी संपूर्ण मानवता के लिए पथ प्रदर्शक है। गीता की शिक्षाएं हमें कर्तव्य, धैर्य, आत्मबल, कर्मयोग, मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। डॉ. शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर तीन दिवसीय महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया तथा गीता के पवित्र ग्रंथ पर पुष्प अर्पित किए।

आईएमटी मानेसर में किसान कैंटीन शुरू

चंडीगढ़। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचएसआईआईडीसी) ने आईएमटी मानेसर में सेक्टर-4 और सेक्टर-5 स्थित दो अटल श्रमिक किसान कैंटीनों को संचालित कर दिया है। इन कैंटीनों के शुभारंभ के साथ क्षेत्र में श्रमिक कल्याण सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एचएसआईआईडीसी द्वारा आईएमटी मानेसर में कुल पाँच स्थानों की पहचान अटल श्रमिक किसान कैंटीन योजना के तहत की गई है। शेष तीन कैंटीनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें आने वाले सप्ताहों में शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद श्रमिकों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

अंबाला में मंत्री अनिल विज ने एचएसओ की पीठ थपथपाई

चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला कैंट में एक कार्यक्रम के बाद कैंट थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार की पीठ थपथपाई। मंत्री विज ने पुलिस अफसर को यह शाबाशी क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ के आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनका सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाने की कार्रवाई पर दी। इसके साथ ही मंत्री विज ने कहा कि अंबाला छावनी में गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा- महिलाएं और बच्चियां जब चाहें, जहां चाहें सुरक्षित रूप से जा सकती हैं। गौरतलब है कि दो दिन पहले मंत्री अनिल विज ने इन्हीं थाना प्रभारी को जन सुनवाई करते हुए फटकार लगाई थी। उन्होंने पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

खिलाड़ी की मौत पर सरकार गंभीर, खराब-जर्जर स्टेडियमों में कोई खेल एक्टिविटी नहीं होगी

हरिभूमि ब्यूरो ▸▸ चंडीगढ़

हरियाणा की नायब सैनी सरकार रोहतक में पोल गिर जाने के बाद में हुई एक खिलाड़ी की मौत के बाद में एक्शन में है। अब जर्जर और खेलने लायक मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की सूरत में इस तरह के स्थानों पर खेल गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि कंडम स्टेडियमों में कोई खेल गतिविधि नहीं कराई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पहले ही जांच पड़ताल और हालात पर पूरा अपडेट ब्यौरा भेजने को कहा था। मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस पर लंबी मंत्रणा के बाद गंभीरता दिखाते हुए कई कदम उठाए हैं।राज्य की नायब सैनी सरकार खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। साथ ही हाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि किसी भी लापरवाह अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री गौरव गौतम ने भी घटनाक्रम के बाद में दो अधिकारियों पर गाज गिरा दी थी।

सुधार के लिए 114 करोड़ जारी

आने वाले वक्त में इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हो इसको लेकर खास कदम उठाए जा रहे हैं। सूबे की नायब सैनी सरकार ने स्टेडियमों और खेल परिसरों के सुधार के लिए 114 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सभी स्टेडियमों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। उन्हें चार श्रेणियों में बांटा जाएगा। फर्जी खेल नर्सरियों पर भी रोक लगाई जाएगी। सरकार अब पूरी तरह जाग चुकी है। प्रदेश में किसी भी स्टेडियम या खेल मैदान की दशा 'कंडम' पाई गई तो वहां किसी भी प्रकार की खेल गतिविधि या अभ्यास की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी।

सभी की जांच पड़ताल का आदेश

मैदानों का कायाकल्प किया जाए : खेल मंत्री

पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि प्रदेशभर में स्टेडियमों और खेल परिसरों के उन्नयन, मरम्मत और पुनर्विकास के लिए 114 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। जिला खेल परिषदों को भी निर्देश दिया गया है कि उनके पास उपलब्ध राशि का बड़ा हिस्सा जिला स्तरीय मैदानों के कायाकल्प में लगाया जाए।

रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें

मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खेल विभाग सभी स्टेडियमों का वैज्ञानिक सर्वे कर उन्हें चार कैटेगरी में इस प्रकार करेगा वर्गीकृत ए ग्रेडः उत्कृष्ट एवं अभ्यास योग्य बी ग्रेडः सामान्य, खेलने योग्य सी ग्रेडः मरम्मत के बाद उपयोग योग्य डी ग्रेडः पूरी तरह बंद, खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित होगा। गौतम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और हुडा के अंतर्गत आने वाले सभी खेल मैदानों और स्टेडियमों की तत्काल संयुक्त जांच की जाए और विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाए। लापरवाही पर संबंधित जिला खेल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तय होगी।

गोलमाल करने और फर्जी नर्सरियों पर कसेंगे लगाम

राज्यमंत्री गौरव गौतम भी खिलाड़ी की मौत के बाद में गंभीर हैं। उन्होंने खेल सुविधाओं के सुधार के साथ ही फर्जी खेल नर्सरियों पर पूरी तरह रोक लगाम लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि वह स्वयं प्रगति रिपोर्ट की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे ताकि लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे।

भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में विधि प्रकोष्ठ का सेमिनार हुआ

देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बना हरियाणा : नायब सैनी

सीएम बोले - प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलीयन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा

हरिभूमि ब्यूरो ▸▸ चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य एक राष्ट्रवादी विचार, जन आंदोलन और राष्ट्रीय जागरण है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करके ही देश को हर तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी शनिवार को पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में विधि प्रकोष्ठ के समिनार को संबोधित कर रहे थे। सेमिनार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गोपाल शर्मा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संयोजक पर्व शर्मा भी मौजूद रहे।

सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलीयन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के हर नागरिक को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना होगा। चाहे उद्योग, शिक्षा, कौशल, व्यापार, हमारा वाणिज्य, तकनीकी, प्रोद्योगिकी के अलावा हर क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा।

7 लाख 66 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग

हरियाणा में 7 लाख 66 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं और इन उद्योगों ने लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए गतिशील जनसांख्यिकी भी एक स्तंभ है। भारत के युवा और उत्साही आबादी देश के विकास की ऊर्जा बने इसका मूल मंत्र है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला होना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए कानूनी और नियामक सरलीकरण के माध्यम से ई-डूइंग बिजनेस का इको सिस्टम भी तैयार किया है। यह कानूनी रूपरेखा उद्यमियों में हमारी सरकार के प्रति विश्वास को और बढ़ाती है। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत उद्यामियों को 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहुंचाने का काम भी किया है।

घर-घर स्वदेशी हमारा लक्ष्य : बड़ौली

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि स्वदेशी संकल्प एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। हम अपने देश में बने उत्पादों को अपनाएं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी हमारा मंत्र है, हमारा लक्ष्य है और हमारी शक्ति है।

स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें : अलका

भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कहा जब हम स्वदेशी अपनाते हैं, तो हम अपने देश की मिट्टी से जुड़ते हैं, अपने लोगों की मेहनत को सम्मान देते हैं. और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। जब तक यह स्वदेशी नहीं होगी, यह न तो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और न ही न्याय की गारंटी दे सकती है।

जन भागीदारी जरूरी : फणीन्द्रनाथ

संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा ने सेमिनार में बोलते हुए कहा कि स्वदेशी का मतलब सिर्फ भारत में बनी वस्तुओं को प्रयोग करना नहीं है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था में नया मूल्य जोड़ने और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने का मंत्र है। जब हम अपने उद्योगों को मजबूत करते हैं, कौशल और तकनीक को बढ़ावा देते हैं, तो हम न सिर्फ आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि दुनिया को भी शक्ति का परिचय देते हैं। इसमें सभी लोगों की जन भागीदारी आवश्यक है।

आत्मनिर्भर भारत नारा नहीं, 21 वीं सदी का राष्ट्रीय संकल्प : सीएम

पंचकूला में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल नारा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत को अग्रणी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प है। सैनी ने कहा कि हरियाणा ने देश को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है और राज्य अब विविधीकरण, दलहन–तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। उद्योग क्षेत्र में 'हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल' उद्यमियों को योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध करा रहा है। 12 लाख से अधिक एमएसएमई द्वारा 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है तथा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों के अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डेमोग्राफी को महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि हरियाणा का लक्ष्य नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले युवा तैयार करना है। 'हरियाणा स्टार्टअप नीति–2022' के बाद राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1.14 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है और 2,000 करोड़ रुपये का 'फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया जा रहा है।

डॉक्टरों की नाराजगी जारी सीएम से हस्तक्षेप की मांग

- हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज संगठन आंदोलन तेज करने की तैयारी में

हरिभूमि ब्यूरो ▸▸ चंडीगढ़

हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों के संगठन हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के बैनरतले डॉक्टर आने वाले समय में भी आंदोलन की राह पर रहेंगे।

एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर डायरेक्ट सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती को फिर से शुरू करने के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि यह प्रक्रिया पहले भी कैडर में गंभीर ठहराव ला चुकी है, जिसके कारण 95 प्रतिशत डॉक्टर पूरे करियर में सिर्फ एक ही प्रमोशन पा सके हैं। एसोसिएशन ने बताया कि पिछली डायरेक्ट भर्ती से प्रमोशनल एवेन्यू बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसके चलते कई डॉक्टरों को नौकरी छोड़कर शैक्षिक सवानिवृत्ति लेना पड़ा। संस्था का कहना है कि देश के किसी भी राज्य में सीनियर मेडिकल ऑफिसर स्तर पर डायरेक्ट भर्ती का प्रावधान नहीं है। इसी आधार पर 2021 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस भर्ती को रोकने के आदेश भी जारी किए थे।

ऑपरेशन ट्रैक डाउनः 22 दिन में 7500 से अधिक अपराधी जेल भेजे

- गुरुग्राम की 99 .99 प्रतिशत सफलता दर, रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारियां हुई

हरिभूमि ब्यूरो ▸▸ चंडीगढ़

अपराध के खिलाफ निर्णायक जंग में हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू किया गया 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' अब एक ऐतिहासिक सफलता बन चुका है। इस अभियान का उद्देश्य अपराध की जड़ों को काटना और राज्य में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना था और पुलिस ने इसे बेहतरीन ढंग से पूरा किया है। अभियान की तेज़ और योजनाबद्ध कार्रवाई ने अपराधियों के हौसले तोड़ दिए हैं। अब तक 3066 कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य मामलों में लगातार चल रही धरपकड़ से 4521 अतिरिक्त आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर, इस ऑपरेशन के दौरान 7587 अपराधियों को पकड़कर हरियाणा पुलिस ने कानून के शासन को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि यह मिशन न केवल व्यापक है, बल्कि प्रभावशाली भी है, जिसने अपराध पर सख्त प्रहार करते हुए अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि हरियाणा में कोई भी अपराध बिना जवाबदेही के नहीं बचेगा।

राव नरेंद्र सिंह

धान घोटाला : भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलने वाला खुलासा

चंडीगढ़। हरियाणा में सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से सामने आया 80 करोड़ रुपये का धान घोटाला पूरे राज्य में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, और अब हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस प्रकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर, 80 करोड़ रुपये तक का धान घोटाला उजागर होना यह साबित करता है कि भाजपा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। न तो सरकारी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी है और न ही निगरानी तंत्र अपनी भूमिका निभा रहा है। यह घोटाला लापरवाही का परिणाम नहीं, बल्कि संगठित लूट का उदाहरण है।

कुमारी सैलजा

लटकाया जा रहा है फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि पहले तो प्रदेश की सरकार ने किसानों को पोर्टल-पोर्टल के खेल में उलझाया हुआ है तो फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के नाम गिरदावरी- गिरदावरी खेल रही है। मुआवजे के नाम पर किसानों को अभी तक तारीख पर तारीख दी जा रही है। अभी तक गिरदावरी का काम पूरा नहीं हुआ तो मुआवजा कैसे मिल सकता है। किसानों के साथ मजाक करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हरियाणा में बाढ़ की आपदा को पूरे छह माह बीत जाने के बावजूद किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है।

मुख्य सचिव ने आवारा कुत्तों, बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर की समीक्षा बैठक

पालिकाएं और जिले कुत्तों के आश्रय बनाएं 24 घंटे की हेल्पलाइन भी स्थापित करें

हरिभूमि ब्यूरो ▸▸ चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक बैठक में सभी विभागों, नगरपालिका निकायों और जिला प्रशासन को 11 अगस्त, 22 अगस्त और 7 नवंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवारा कुत्तों, बेसहारा पशुओं के प्रबंधन और राजमार्गों तथा सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा के संबंध में जारी किए गए आदेशों को तत्काल और कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरपालिका निकायों और ग्रामीण स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों से लैस कम से कम 5,000 कुत्तों को समायोजित करने में सक्षम बड़े कुत्ता आश्रय स्थल संचालित करें। हर जिला और स्थानीय निकाय आवारा कुत्तों, कुत्ते के काटने, बचाव कार्यों और छोड़ने से संबंधित शिकायतों के लिए 24 घंटे की सुविधा वाली हेल्पलाइन स्थापित करेगा। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नसबंदी, टीकाकरण, टैगिंग और नियमित पशु-चिकित्सा देखभाल पूरी तरह से पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुरूप हो। साथ ही, पकड़ने वाली टीमें पर्याप्त हों और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग सिस्टम अनिवार्य है।

हाईवे से लावारिस पशुओं को हटाया जाए

राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेस- वे से लावारिस पशुओं को हटाने के लिए एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), परिवहन, नगरपालिका निकायों और पशुपालन विभाग को निरंतर संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्राधिकरणों को पुलिस थानों और जिला नियंत्रण कक्षों से जुड़ी, चौबीसों घंटे काम करने वाली हाइवे पेट्रोल टीमें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सड़क किनारे हेल्पलाइन नंबर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

रैलियों में गई बसों का भुगतान लेने के लिए हाई कोर्ट का सहारा, निजी बस संचालक बोले

रैली में बसें चाहिए तो राजस्थान-पंजाब की तर्ज पर पॉलिसी लाए सरकार

- निजी बस संचालकों ने विचार मंथन के बाद में एक बार फिर जोरशोर से मामला उठाने का किया फैसला
- आरोप : सीईटी परीक्षा के लिए ली गई निजी बसों के बदले डीजल का पैसा तो मिला, लेकिन बाकी खर्चे और बकाया का नहीं किया गया अभी तक भुगतान

योगेंद्र शर्मा ▸▸ चंडीगढ़

सियासी रैलियों और परीक्षाओं आदि कार्यों के लिए ली जाने वाली निजी बसों के बदले में उनका बकाया भुगतान नहीं होने पर बस संचालकों ने हुंकार भरी है। निजी बस संचालकों में नाराजगी व्याप्त है। राज्य अध्यक्ष का कहना है कि वे अपनी लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, उसके बाद भी पिछले दिनों हुए सीईटी परीक्षा में उन्होंने सहयोग किया, उन्हें डीजल तो दिया वो भी कम लेकिन उनके अन्य खर्चों के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखाया जा रहा है। बस आपरेटरों ने मुख्य सचिव द्वारा लिखित एक पत्र की कॉपी भेजकर मुख्यमंत्री और आला अफसरों से उन्हें तुरंत ही न्याय दिलाने की मांग उठाते हुए राजस्थान और पंजाब की तर्ज पर नीति बनाने की मांग उठाई है। हरियाणा निजी बस ऑपरेटर एसोसिशएन के प्रदेशाध्यक्ष डा. धन सिंह और पदाधिकारियों राजू शर्मा ने निजी बसों को परीक्षा, सरकारी कामों, रैलियों के लिए जाने की एवज में ठोस पालिसी बनाने की मांग की है। इनका दावा है कि राजस्थान और पंजाब में इस तरह की पालिसी है। बताया जा रहा है कि राज्य में 15 सौ के करीब निजीम मालिकों की बसें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा तीन सौ के करीब बसें सहकारी समितियों द्वारा उन मार्गों पर चलाई जा रही हैं, जहां पर राज्य सरकार की ओर से बसों की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। उधर, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का कहना है कि मामले को दिखवाया जाएगा, उसके बाद ही इस पर कोई जवाब दे सकूंगा। अफसरों के साथ में बातचीत करेंगे।

850 करोड़ अभी भी बकाया

निजी बस संचालकों का कहना है कि लगभग 18 सौ बसें निजी लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। जिसमें 15 सौ निजी ऑपरेटरों की और तीन सौ करीब सहकारी समितियों की हैं। रैलियों और परीक्षा आदि में अधिकांश बसें ली जाती हैं। हिसार और झज्जर, रोहतक जैसे जिलों में सबसे ज्यादा निजी बसें निजी बसों की बात करें, तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा हिसार में 227 और झज्जर में 227 झज्जर में 198 है। रोहतक में 170 बसें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा अंबाला सोनीपत और अन्य कई जिलों में बसों का संचालन अच्छा खासी संख्या में हो रहा है। 850 करोड़ की राशि गत आठ सालों से बकाया है, जिसके लिए हम धक्के खाने को मजबूर हैं।

रैलियों और कार्यक्रमों में जाती हैं बसें

राज्य अध्यक्ष का कहना है कि राज्य सरकार की तमाम रैलियों, कईं परीक्षाओं, महापुरुषों की याद में होने वाले कार्यक्रमों राज्यस्तरीय में हमेशा ही बसें जाती हैं। लेकिन चालक परिचालकों और बसों की मुरम्मत, कईं बार बसों में नुकसान भी रैलियों के दौरान होता है। 2018 से उनकी राशि लगातार बढ़ी और भुगतान नहीं हुई, तो उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी। 2023 में लगाई गई याचिका पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अपनी रोडवेज की बसों पर होने वाले खर्च और उनको दिए जाने वाले भुगतान की तर्ज पर राज्य सरकार हमारे साथ भी वही व्यवहार करे। हमने सीईटी की परीक्षा के लिए भी सबें दी राज्य सरकार का सहयोग किया लेकिन उसका भी बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है।

मेरे पास अभी तक मामला नहीं आया

प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि अभी तक मेरे पास बकाया मामले में निजी बसों के संचालक नहीं आए हैं। जब आएंगे तो अधिकारियों के साथ बातचीत कर उसका समाधान कराया जाएगा। विज ने समय के मामले में कहा कि वे तो रोजाना ही लोगों की सुनवाई करते हैं, मेरे दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हैं। रात दिन सुनवाई करता हूं और जनता के बीच में रहता हूं।

कई श्रेणियों में मुफ्त करवा रहे यात्रा

प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि निजी बस संचालक निजी बस संचालकों में भी उन श्रेणियों को यात्रा मुफ्त करा रहे हैं, जिनके लिए राज्य सरकार ने रोडवेज में छूट दी है। इसी तरह से निजी बस संचालक रियायती बस पास भी विद्यार्थियों के निजी बसों के लिए अलग से बनाते हैं। इसकी एवज में जो भी आर्थिक नुकसान उन्हें होता है, उसका भुगतान वे लंबे इंतजार और चक्कर लगाने के बाद में संबंधित विभाग से लेते हैं। अध्यक्ष डा. धन सिंह ने बताया कि लगभग 40 श्रेणियों को यात्रा कराई जाती है। इसमें तीस निशुल्क और दस रियायती पास वाले हैं। हम निशुल्क पास का भुगतान संबंधित विभाग से लेते हैं, जबकि रियायती पास पर दी गई छूट का पैसा भी विभागों से लिया जाता है।

10 जिलों में 1 हजार 479 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

चंडीगढ़। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की दिसंबर सत्र की परीक्षाएं 01 दिसम्बर 2025 से पूरे भारत में शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक संचालित होंगी। इग्नू द्वारा सभी पात्र परीक्षार्थियों के हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें विद्यार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट से अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से समर्थ पोर्टल पर किसी परीक्षार्थी को हॉल टिकट डाउनलोड करने की परेशानी आती है, तो वह इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल से सीधे संपर्क कर सकता है। करनाल के अंतर्गत इस वर्ष कुल 172663 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, पानीपत और रोहतक में कुल 33 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 परीक्षा केंद्र हरियाणा की विभिन्न जेलों में बनाए गए हैं, जहां कुल 1479 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

रोहतक
रविवार, 30 नवंबर, 2025
मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष
दशमी वर्ष : 29, अंक : 301
पृष्ठ 14 मूल्य 3.00

मौसम
अधि. 26.5
न्यून. 7.8

हरिभूमि
हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित
समाचार ही नहीं, विचार भी
haribhoomi.com

आज भारतीय तटों से टकराएगा दितवाह तूफान

आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु में भारी बारिश, पुद्दुचेरी में परीक्षाएं रद्द

आईएमडी का यलो अलर्ट जारी

एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात, खोजी कुत्तों के दल भी शामिल किए

चक्रवाती तूफान दितवाह को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह 30 नवंबर को तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा।

खबर संक्षेप

रेलवे एप डाउन, नहीं हुई टिकट की बुकिंग

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी की वेबसाइट व एप पिछले 96 घंटों यानी करीब चार दिनों से बंद पड़ी रही। सुबह से शाम तक हर कोशिश नाकाम साबित हुई। यूजर्स को बार-बार वही पुराना एरर मैसेज दिखाई दिया। डाउन डिटेक्टर जैसी साइट्स पर चेक करने पर साफ दिख रहा था कि सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम जीरो है मतलब कि सर्वर जवाब ही नहीं दे रहा। शनिवार दोपहर 2 बजे से शुरू हुई तत्काल बुकिंग का समय भी बीत गया, लेकिन कोई टिकट नहीं बिकी। *एजेंसी*

62 के पीएम ने 46 साल की हेडन से की शादी

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने अपने आवास पर करीबी लोगों की मौजूदगी में जोडी हेडन से विवाह किया। ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के 124 साल के इतिहास में वह ऐसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान विवाह किया है। 62 वर्षीय अल्बनीज और 46 वर्षीय हेडन ने कहा, हम अपने विवाह से खुश हैं। अपनी जिंदगी साथ बिताने का वादा करके बहुत खुश हैं। अल्बनीज तलाकशुदा हैं। उनका एक बेटा है। *एजेंसी*

एक्यूआई@ 329

बहादुरगढ़ 322, धारूहेड़ा 309
नोएडा 310, दिल्ली 305, दादरी 304

आबोहवा खराब, सोनीपत देश का सबसे प्रदूषित शहर

हरिभूमि न्यूज ▶▶| सोनीपत

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। शनिवार को सोनीपत की हवा देश में सबसे खराब दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को सोनीपत का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 329 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। इस चिंताजनक स्थिति ने न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि चिकित्सकों की भी चिंता बढ़ा दी है। एक ओर जहां प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे मौसम में गरमाहट महसूस हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सक भी आम आदमी को सतर्क रहने के सलाह दे रहे हैं। वहीं दिल के मरीजों और सांस के मरीजों को तो घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

प्रदूषण बढ़ने से आंखों में जलन और हो रही एलर्जी

अस्थमा से पीड़ित मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह

ऐसा रहा प्रदूषण का स्तर

देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शनिवार को सोनीपत शीर्ष पर रहा। यहां का एक्यूआई 329 दर्ज किया गया। इसके बाद अन्य एनसीआर और हरियाणा के शहर भी इसी श्रेणी में शामिल रहे, जिनमें बहादुरगढ़ 322 एक्यूआई, हापुड़ (नोएडा के पास) 310 एक्यूआई, और धारुहेड़ा 309 एक्यूआई के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि समूचे क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है।

बदल रहा मौसम

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह बढ़ोतरी एक दिन पहले के तापमान की तुलना में अधिक है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस था। यानी अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।

चिकित्सकों ने चेताया

चिकित्सक डॉ. जेएस पूनिया ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 300 से ऊपर का एक्यूआई स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने विशेष 5तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और हृदय/श्वसन संबंधी रोगों (जैसे अस्थमा, सीओपीडी) से पीड़ित मरीजों के लिए चेतावनी जारी की है।

ये सावधानियां बरतें

- सुबह और शाम के समय अनावश्यक बाहर न निकलें।
- अनिवार्य रूप से एन95 या केएन95 मास्क लगाएं।
- खूब पानी पीएं, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहें।
- आहार में ऐसे तत्वों को शामिल करें, जो फेफड़ों को मजबूत बनाए।
- बाहर जॉगिंग या जोरदार व्यायाम करने से बचें।
- श्वास के रोगी दवाएं और इनहेलर नियमित लें।

प्रदेश में 2 दिन बाद चलेगी शीतलहर

हिसार। प्रदेश में 2 दिन बाद एक दिसंबर से धुंध और ठंड दोनों बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दो दिन बादल छाएंगे। 1 दिसंबर से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से नमी बढ़ सकती है। इससे धुंध बढ़ेगी और शीतलहर चलेगी। इस दौरान रात के तापमान में गिरावट आएगी। नारनौल राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां बीती रात को न्यूनतम तापमान 7.8° डिग्री दर्ज किया गया।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की बैठक में महमूद बोले, मुसलमान देश में बराबर के नागरिक

आरोप-सुप्रीम कोर्ट 'सुप्रीम' कहलाने लायक नहीं

मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर कहा-जुल्म होगा तो जिहाद होगा

भोपाल (हरिभूमि न्यूज)। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सीधे कहा कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। देश की अदालतें हुकूमतों के दबाव में फैसला दे रही हैं। बीते कुछ अरसे से खासकर बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और कई अन्य मामलों में फैसलों के बाद ऐसा ही लगता है। उन्होंने आरोप लगया कि सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसी इस्लाम की पवित्र अवधारणा को दुर्व्यवहार, अव्यवस्था और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। लव जिहाद, भूमि जिहाद, शिक्षा जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते है।

पात्रा बोले- बयान भड़काऊ ही नहीं, समाज को भी बांटने वाला

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मदनी के बयान पर कहा कि उनका बयान भड़काऊ और देश को बांटने वाला है। जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी आतंक फैलाया है, वह हमने देखा है। मौलाना के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर इसकी सुनवाई करनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सम्मान...

हरियाणा पवेलियन को मिला स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले-2025 में हरियाणा को स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल मिला है। व्यापार मेले में अलग-अलग श्रेणियों में मेडल दिए गए थे, इसमें हरियाणा प्रदेश के पवेलियन ने स्वच्छ मंडप में बाजी मारी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंडप के निदेशक अनिल चौधरी ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक 14 दिन चले इस 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। पवेलियन में हरियाणवी संस्कृति, निरंतर जारी इनोवेशन और प्रदेश के विकास की झलक देखने को मिली।

14 दिन चले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हजारों लोगों ने देखी हरियाणवी संस्कृति, इनोवेशन और डेवलपमेंट की झलक

सॉफ्टवेयर हो रहा अपडेट...

भारत में इंडिगो, एअर इंडिया समूह की 338 फ्लाइट्स प्रभावित

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस के ए320 सीरीज के एयरक्राफ्ट्स पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई, डायरेक्शन, कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। इस तकनीकी खराबी से बचने के लिए फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल ए320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके कारण दुनिया भर में 6,000 विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण भारत में अब तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है, लेकिन कुछ उड़ानों में 60-90 मिनट की देरी हो रही है।

एयरबस के ए320 विमानों में सोलर रेडिएशन का खतरा

कैथल कोर्ट का अहम फैसला...

दुष्कर्मी पिता को अंतिम सांस तक जेल की सजा

कैथल (हरिभूमि न्यूज)। दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के दोषी पिता को अंतिम सांस तक कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी मामले में एक अन्य दोषी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा की गई है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की सजा अलग से भुगतनी होगी। अतिरिक्त सेशन जज अनूपमिश मोदी ने अदालत ने डीएलएसए की मार्फत पीड़िता को सात लाख रुपए मुआवजे के भी आदेश दिए हैं। पीड़ित लड़की ने अपने दर्ज बयान में बताया कि उसका पिता ही उसे अंबाला लेकर गया। वहां उसके पिता ने अनेक बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

पिता पर एक लाख जुर्माना भी
●
एक अन्य दोषी को 20 साल की कैद

जांच में दुष्कर्म का दोषी पाया

पीड़ित ने बताया कि पिता ने कैथल व गुहला में भी उसके साथ दुष्कर्म किया। एक अन्य युवक गुरजंट ने भी अप्रैल 2022 में उसके साथ दुष्कर्म किया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों को दुष्कर्म का दोषी पाया और पिता को अंतिम सांस तक और गुरजंट को बीस साल की सजा सुनाई।

दिल्ली धमाका-आतंकी शाहीन के फ्लैट से मिला 18.50 लाख कैश

■ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट लॉकर में छिपाए थे रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी कर रही है। इसी कड़ी में आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉ. शाहीन सईद के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट से 18.50 लाख कैश सहित सोने के बिस्किट और गहने मिले है। अलमारी से अरब देशों की करेंसी भी मिली है। जांच एजेंसी गुरुवार को शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। टीम ने यहां पर उसकी गतिविधियों की जांच की। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन का 22 नंबर फ्लैट है। इस फ्लैट में वह काफी समय तक रही। जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर सीक्रेट लॉकर मिला। इसको खुलवाया गया तो अंदर कई पैकेट रखे हुए थे। इन पैकेट में 500-500 रुपए के नोट थे। टीम ने पैसे गिने तो ये 18.50 लाख रुपये निकले।

सोने के 2 बिस्कुट, 300 ग्राम जेवर मिले

टीम ने अलमारी के दूसरे लॉकर की तलाशी ली। इसमें सोने के 2 बिस्कुट के साथ करीब 300 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए। सूत्रों ने ये भी बताया कि अलमारी से अरब देशों की करेंसी भी मिली है। डॉ. शाहीन के कई करीबी फंडिंग के लिए कई गैर-सरकारी संगठन के संपर्क में थे।

बच्चों के झगड़े में ताऊ को स्कॉर्पियो से कुचला पिता और पुत्र ने नाले में कूद बचाई जान

गांव के ही चार युवकों पर ही हत्या का आरोप

कनीना (हरिभूमि न्यूज)। कनीना विकास खंड के गांव नोताना में बच्चों की आपसी कहासुनी में एक व्यक्ति की जान चली गई। नोताना निवासी जोगेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके भतीजे हैप्पी व उसके साथी कुलदीप तथा नवीन का गांव के ही नीरज, अंकित, सतेंद्र व विशाल उर्फ छोटू ये झगड़ा हो गया। इस दौरान जोगेंद्र व सूबेसिंह बच्चों के साथ घर की ओर चले तो आरोप है कि उपरोक्त चारों युवक दोबारा से योजना बनाकर गाड़ी में सवार होकर आए तथा जान से मारने की नियत से स्कॉर्पियो गाड़ी की तेज गति से टक्कर मारी। जोगेंद्र व बच्चों ने नाले में कूद कर अपनी जान बचाई, जबकि उसके भाई सूबेसिंह 58 वर्ष को सीधी टक्कर लगी। स्कॉर्पियो को नीरज चला रहा था। गंभीर चोटें लगने के कारण सूबेसिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपित गाड़ी को लेकर धमकी देते हुए स्याणा गांव की ओर फरार हो गए। जोगेंद्र ने बताया कि हैप्पी व उसके साथियों के साथ मारपीट करने के बाद रंजिशवश आरोपितों ने हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया है।

संबोधन 'राष्ट्र' की हमारी अवधारणा पश्चिमी से काफी अलग

दुनिया के अन्य हिस्से संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में हुए विकसित

भारत की परंपरा भाईचारे में निहित विवाद हमारे स्वभाव में नहीं : भागवत

मुंबई (भाषा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि विवादों में उलझना भारत के स्वभाव में नहीं है और देश की परंपरा ने भाईचारे एवं सामूहिक सद्भाव पर हमेशा जोर दिया है। भागवत ने नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में कहा कि राष्ट्र की अवधारणा के मामले में भारत का दृष्टिकोण पश्चिमी व्याख्याओं से मूलतः भिन्न है। उन्होंने कहा, ''हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। हम विवादों से दूर रहते हैं। विवाद करना हमारे देश के स्वभाव में नहीं है। एकजुट रहना और भाईचारे को बढ़ावा देना हमारी परंपरा है।'' उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्से संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में विकसित हुए हैं।

एकजुटता का किया आह्वान

हम अन्य विचारों के लिए बंद कर देते हैं दरवाजे

भागवत ने कहा, ''एक बार कोई मत बन जाने के बाद उससे अलग कोई भी विचार अस्वीकार्य हो जाता है। वे अन्य विचारों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं और उसे 'वाद' कहकर पुकारने लगते हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र की अवधारणा को लेकर भारत का दृष्टिकोण पश्चिमी व्याख्याओं से मूल रूप से भिन्न है। उन्होंने कहा, ''वे राष्ट्र की हमारी अवधारणा को समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने इसे 'राष्ट्रवाद' कहना शुरू कर दिया। 'राष्ट्र' की हमारी अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है....।'' उन्होंने कहा, ''हम राष्ट्रीयता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रवाद का नहीं। राष्ट्र के प्रति अत्यधिक गर्व के कारण दो विश्व युद्ध हुए और यही कारण है कि कुछ लोग राष्ट्रवाद शब्द से डरते हैं।''

भारत हमेशा से एक 'राष्ट्र' रहा

भागवत ने कहा कि यदि राष्ट्र की उस परिभाषा को माना जाये, जो पश्चिमी संदर्भ में समझी जाती है, तो उसमें आमतौर पर एक राष्ट्र की व्यवस्था होती है, जिसमें केंद्र सरकार क्षेत्र का संचालन करती है, लेकिन भारत हमेशा से एक 'राष्ट्र' रहा है, चाहे अलग-अलग शासन-व्यवस्थाएं रही हों या विदेशी शासन का समय रहा हो। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत की राष्ट्रीयता अहंकार या अभिमान से नहीं, बल्कि लोगों के बीच गहरे अंतर्संबंध और प्रकृति के साथ उनके सह-अस्तित्व से उपजी है।

खबर संक्षेप

फरीदाबाद। फोन हैक कर खाते से पैसे निकालने के आरोपी साईबर थाना बल्लभगढ़ की गिरफ्त में।

खाते से पैसे निकालने के मामले में तीन पकड़े

फरीदाबाद। साइबर थाना बल्लभगढ की टीम ने फोन हैक कर खाता से पैसे निकालने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर-7 फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 15 सितम्बर को उसके पास कथित सैमसंग कस्टमर केयर कर्मचारी का फ्रिज के रूटीन चैक अप के लिए कॉल आया। जिसके कुछ देर उन्होंने उसके पास फोन पर एक लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करते ही उसका फोन हैक हो गया और उसके बैंक खाता 1,81,862 कट गये। जिस शिकायत पर साइबर थाना बल्लभगढ में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

टास्क से ठगी के मामले में खाताधारक गिरफ्तार

फरीदाबाद। साइबर थाना बल्लभगढ की टीम ने कार्रवाई करते हुए टेलिग्राम टास्क के नाम पर ठगी के मामले में खाताधारक गोविंदा को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके फेसबुक पर पार्ट टाइम जॉब के लिए लिंक आया, जिस पर क्लिक करने के बाद वह एक टेलिग्राम ग्रुप से जुड गया। जहां से उससे लिंक भेज एक एप डाउनलोड करवाया और टास्क करने को दिये गये। जिसके बाद उन्होंने उसे पैड टास्क कर अधिक पैसे कमाने का लालच दिया। जिसके लिए उसने उनके बताये खाता में विभिन्न ट्रांजेक्शन के माध्यम से 1 लाख भेज दिए।

ऑपरेशन सिंदूर पर सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह बोले

दुश्मन ने 90 घंटे में घुटने टेक दिए, नहीं तो एक्स सर्विसमैन को वापस बुलाते

हरिभूमि न्यूज ▶▶ हिसार

सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे ऊपर एक मुश्किल टाइम आया था। हमारे देश में आंतकवादी हमला हुआ और पूरा देश सैनिक कार्रवाई करने की तरफ देख रहा था कि सेना अब क्या कार्रवाई करती है।

हम लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, मगर हमने देखा कि लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। 90 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए थे। लड़ाई लंबी चलते तो एक्स सर्विसमैन को वापस बुलाना पड़ता। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह शनिवार को हिसार मिलिट्री स्टेशन में एक्स सर्विसमैन रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के अंतर्गत डॉट ऑन टारगेट डिवीजन द्वारा हिसार मिलिट्री स्टेशन में हरियाणा के दस जिलों हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक के लिए एक पूर्व सैनिक रैली और चिकित्सा शिविर में शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, वीर माताओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया।

हिसार मिलिट्री स्टेशन में पूर्व सैनिक रैली का आयोजन लेफ्टिनेंट जनरल ने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, वीर माताओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया

हिसार : कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को स्मृति चिन्ह देते लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह।

लड़ाई की शक्ल बहुत बदली, अब हो रहे साइबर अटैक

लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आने वाले समय में लड़ाई का तरीका बदल रहा है। पहले लड़ाई सिर्फ मिलिट्री लड़ा करती थी। मिलिट्री उसका जवाब देती थी। आज के दिन लड़ाई की शक्ल बहुत बदल चुकी हैं। इसको नॉन कांटेक्ट वार फेयर और कांटेक्ट वार फेयर बोला जाता है। अभी साइबर अटैक को रहा है मगर आपको मालूम नहीं कहां से हो रहा है, लेकिन आप इसके खतरे से खाली नहीं है। हाल ही में देखा एयरपोर्ट की पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक्सीडेंट हो सकता है। रेलवे सिग्नल में प्राब्लम हो सकती है। टारगेट का मिसाइल चूक सकता है। यह खतरे बढ़ चुके हैं। इसलिए टारगेट भी बढ़ चुके हैं। आज की लड़ाई में पूरा देश शामिल होता है। सिविल ऑफ मिल्ट्री को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है।

देश में 20 वेटरन्स हॉस्पिटल का निर्माण होगा

लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि सर्विसमैन तथा एक्स सर्विसमैन के लिए वेटरन्स हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। सैनिक के रिटायर होने के बाद सरकार पूर्व सैनिकों तथा उसके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। वर्तमान में जरूरत पड़ने पर पूर्व सैनिकों शहरों में सरकार से इन पैनल हॉस्पिटल में इलाज भी करवाते हैं। इस सुविधा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए वेटरन्स हॉस्पिटल प्रोजेक्ट बनाया गया है। वेटरन्स हॉस्पिटल में मरीजों को इनडोर तथा आउटडोर दोनों तरह से सुविधा दी जाएगी। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में 20 वेटरन्स हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा।

थाना मालखाने से गबन के आरोपित पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्तः एसपी

19 सितंबर को सदर थाना के मालखाना में रखे माल मुकद्मों को निरीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि मालखाने से 23 लाख नगदी व जेवरात में से दो अंगूठी गायब मिलीं थी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ जींद

■ पुलिस ने आरोपितों से रिकवर किए साढ़े नौ लाख रुपये, 23 लाख के गबन का आरोप

सदर थाना मालखाना से लाखों रुपये की राशि तथा जेवरात हडपने के आरोपित दोनों बर्खास्त पुलिस कर्मियों को शहर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर साढ़े नौ लाख रुपये की रिकवरी भी की है। दोनों पुलिसकर्मियों को अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डीएसपी संदीप कुमार ने गत 19 सितंबर को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सदर थाना के मालखाना में रखे माल मुकद्मों को निरीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि मालखाने से 23 लाख रुपये की नगदी तथा जेवरात में से दो सोने की अंगूठी गायब हैं। जिस पर उस अवधी के दौरान मालखाने के इंचार्ज हवलदार जोगेंद्र, सिपाही मजीद से जवाब मांगा गया। जो संतोषजनक जवाब नही दे पाए। राशि तथा जेवरात 20 मई 2022 से 18 जून 2025 तक राशि गायब हुई थी। जोकि 56 मुकद्मों का सामान था। शहर थाना पुलिस ने डीएसपी की शिकायत पर हवलदार जोगेंद्र तथा सिपाही मजीद के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन का मामला दर्ज किया था। एसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों को बर्खास्त कर दिया था। शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोगेंद्र तथा मजीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित जोगेंद्र की निशानदेही पर नौ लाख रुपये तथा मजीद की निशानदेही पर पचास हजार रुपये की रिकवरी की है।

जींद। एसपी कुलदीप सिंह।

न्यायिक हिरासत में भेजा

शहर थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। दोनों को निलंबित कर उनके के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया था।

जमीन के रिकार्ड से छेड़छाड़ रिटायर्ड तहसीलदार जार्चशीट

रेवाड़ी। शनिवार को हुई जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर प्रदेश के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल तेवर सख्त नजर आए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले व गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारी सस्पेंड होने के लिए तैयार रहे। उन्होंने परिवादों की सुनवाई करते हुए रिटायर्ड तहसीलदार को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए। कैबिनेट मंत्री गोयल ने भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे, पानी की शुद्धता और खिलाड़ियों की मौत जैसे गंभीर मुद्दों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों और बिल्डरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने परिवाद की सुनवाई करते हुए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में डीटीपी को फटकार लगाई। नप के जमीन पर कब्जों के मामले में ईओ पर नाराजगी जाहिर की। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पुराने व नए 17 परिवादों में से 14 परिवादों पर सुनवाई की गई।

शादी समारोह में डीजे पर विवाद

बीच-बचाव करने पर युवक की नुकीले हथियार से हत्या

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रेवाड़ी

रोहतक पीजीआई में तोड़ा दम

जिले के गांव देहलावास गुलाबपुरा के लगन समारोह में डीजे पर हुई कहासुनी ने एक युवक की जान ले ली। बीच-बचाव करने गए देहलावास गांव के 25 वर्षीय युवक संजीव की शुक्रवार देर रात नुकीले हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। संजीव अपने पड़ोस के गांव में चल रहे लगन समारोह में शामिल होने गया था। वहां डीजे पर देहलावास गुलाबपुरा के दो स्थानीय युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे। संजीव ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया तथा कुछ देर बाद एक युवक घर चला गया, लेकिन बाद में दो युवक संजीव से बीच में बोलने को लेकर झगड़ा करने लगे। इसके बाद दोनों ने संजीव को जबरन बाइक पर बैठाया और गांव के जोहड़ के पास ले जाकर नुकीले हथियार से उसकी कनपटी पर वार कर दिया। संजीव के चिल्लाने की आवाज सुनकर लगन समारोह में मौजूद लोग व परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद घायल संजीव को पहले रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रामपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। संजीव का पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं।

2110 किलो ग्राम कॉपर लूटने के आरोपी काबू

फरीदाबाद। अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने सेक्टर 24 स्थित एक कम्पनी से कॉपर व गाडी की लूट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 23-24 नवम्बर की रात को 5-6 व्यक्तियों ने सेक्टर-24 स्थित त्रिकूटा मेटल्स प्लांट में चौकीदार को बंधक बनाकर करीब 2000 किला तांबा, एक पिक अप गाडी व दो टीवी लूट कर ले गये। जिस पर जतिन चोपडा की शिकायत पर थाना मुजेसर में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आगे बताया कि अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त सन्दीप सुमन व सूरज निवासी मुंदेरी, मुंगेर बिहार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

■ पुलिस रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ

नूंह की विशेष पोक्सो कोर्ट का फैसला

नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट में दो को 10 -10 साल की कैद

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नूंह

■ दोनों पर कुल 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में दो मुख्य आरोपियों को 10 -10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ताहिर और उसकी चाची रहीला उर्फ गुड्डी निवासी थाना सदर जिला नूंह को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया है। विशेष सहायक लोक अभियोजक विजय सहरावत ने बताया कि यह मामला 10 फरवरी 2023 का है। पीड़िता अपनी मां के साथ लकड़ी लेने जा रही थी। ताहिर ने उसे अकेला देखकर उसे जबरन घर में खींच लिया। उसकी चाची रहीला उर्फ गुड्डी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताहिर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत करने पर आरोपी परिवार के 10 -11 लोग पीड़िता के घर में घुसे, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

2 वर्ष 9 माह में फैसला

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने कुल 149 गवाहों व सबूतों के आधार पर सिर्फ 2 साल 9 महीने में फैसला सुना दिया, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तेजी का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि दोनों दोषी अभी जिला कारागार नूंह में बंद हैं और जुर्माना अभी तक जमा नहीं कराया गया है। शुरुआत में ही जांच के दौरान पुलिस सहयोग से इस मामले में सभी जरूरी सबूत एकत्रित कर लिए गए थे।

न्यायालय श्री विजय कुमार यादव एच.सी.एस. बअख्तयारात कलैक्टर प्रथम श्रेणी कोसली।
मिशल नम्बर 95/फकूल रहन
तारीख पेशी 03.12.2025
रामकिशन पुत्र श्रीराम पुत्र प० रामदयाल निवासी ग्राम सुर्खपुर तहसील कोसली जिला रेवाड़ी।
बनाम
1- सुभाष 2- मामन मृतक बजरिये कानूनी वारसान 2ए- संजय 2बी- जय कुमार पुत्रान 2सी- अन्जुबाला पुत्री 2डी- माया देवी विधवा मामन पुत्र रामस्वरूप 3- धर्मबीर पुत्रान रामस्वरूप 4- रूपचन्द बजरिये कानूनी वारसान 4ए- आनन्द 4बी-गोपाल पुत्रान 4सी-बबली 4डी-ममता पुत्रीयान 4ई-रामा देवी विधवा रूपचन्द 5-जगदीश कुमार पुत्रान छाजूराम पुत्र रामप्रसाद 6- श्रीमती गिन्दोड़ी विधवा रामस्वरूप 7- श्रीमती शकुन्तला विधवा लीलाराम उर्फ रूघनाथ 8- आनन्द प्रकाश 9 यशपाल 10- राजकुमार पुत्रान लीलाराम उर्फ रूधनाथ निवासीगण ग्राम सुर्खपुर तहसील कोसली जिला रेवाड़ी।
11- सुरेश कुमार पुत्र सुलतान पुत्र छाजूराम निवासी गली नम्बर 12 आनन्द पर्वत देहली 12-बाला पुत्री लीलाराम धर्मपत्नी श्री बृजेन्द्र वल्द गजानन्द निवासी मौजा साल्हावास तहसील मातनहेल जिला झज्जर। 13- रमेश कुमारी पुत्री लीलाराम उर्फ रघनाथ हाल निवासी मौजा पाटौदा तहसील व जिला झज्जर। 14- सावित्री पुत्री छाजुराम धर्मपत्नी मुरारीलाल 15- वेदकुमारी पुत्री छाजुराम धर्मपत्नी शंकरलाल निवासी मौजा मून्दी तहसील व जिला रेवाड़ी 16- प्रेमवती पुत्री छाजुराम धर्मपत्नी हीरालाल वल्द औमप्रकाश निवासी मौजा हांसाक तहसील व जिला रेवाड़ी 17- औमप्रकाश 18- रोहताश 19- रामौतार पुत्रान विद्यादेवी पुत्री छाजुराम धर्मपत्नी मातुराम निवासीगण मौजा साल्हावास तहसील मातनहेल जिला झज्जर 20 सन्तरा देवी पुत्री रामस्वरूप धर्मपत्नी औमदत 21- भानी देवी पुत्री रामस्वरूप धर्मपत्नी सोमदत निवासीगण मौजा ढोरका जिला रेवाड़ी 22-लीला देवी 23- कृष्णा देवी पुत्रीयान रामस्वरूप निवासीगण मौजा सुरतगढ़ (राजस्थान) 24-कांटी पुत्री रामस्वरूप हाल निवासी मौजा रेढूवास तहसील मातनहेल जिला झज्जर 25-विशिष्ट कुमार पुत्र श्री अनारली धर्मपत्नी हरफूल 26- लक्ष्मी देवी विधवा नित्यानन्द पुत्र अनारली 27- मनोज वल्द नित्यानन्द 28- लक्ष्मीनारायण वल्द नित्यानन्द 29 हंसराज वल्द नित्यानन्द 30- बबली पुत्री नित्यानन्द धर्मपत्नी मेहरचन्द निवासी मौजा सुन्दरोज तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ 31- चन्द्रपति विधवा नरेन्द्र पुत्र अनारली 32- अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र पुत्र अनारली निवासी यादव नगर कंकरवाली रेवाड़ी 33 मधू पुत्री नरेन्द्र धर्मपत्नी शिवकुमार निवासी कंकरवाली रेवाड़ी 34- उर्मिला पुत्री नरेन्द्र पुत्रवधू हरिराम मास्टर निवासी मून्दी तहसील व जिला रेवाड़ी 35- श्रीमती द्वारका विधवा विरेन्द्र 36-सतबीर पुत्र विरेन्द्र पुत्र अनारली निवासीगण मौजा खड़गवास तहसील व जिला रेवाड़ी 37- सुशीला देवी पुत्री बिरेन्द्र हाल निवासी मौजा सुरेहती तहसील व जिला झज्जर 38- लीला देवी पुत्री बिरेन्द्र धर्मपत्नी विनोद निवासी कंकरवाली जिला रेवाड़ी 39- सत्यवती पुत्री औमप्रकाश धर्मपत्नी राधेश्याम वल्द फूल सिंह निवासी मौजा बव्वा तहसील कोसली जिला रेवाड़ी 40 चन्द्रप्रकाश वल्द औमप्रकाश निवासी रामसिंहपुरा रेलवे कालोनी रेवाड़ी 41 कृष्ण कुमार पुत्र अनारली धर्मपत्नी हरफुल निवासी नजदीक रेलवे लोकू शैड रेवाड़ी 42- बलराम पुत्र अनारली पत्नी हरफुल निवासी बूढ़पुर रोड कंकरवाली रेवाड़ी 43 पवित्रा पुत्री अनारली धर्मपत्नी उमेशचन्द्र निवासी रेलवे कालोनी नजदीक लोकू शैड रेवाड़ी 44- रामौतार 45 मानसिंह 46- महाबीर पुत्रान मनभरी धर्मपत्नी नानगराम 47- रेवती पुत्री मनभरी धर्मपत्नी नानगराम निवासीगण मौजा फतेहपुरी दड़ौली तहसील व जिला रेवाड़ी 48-बीरमति पुत्री मनभरी धर्मपत्नी ब्रहमदत निवासी ग्राम दुबलधन जिला झज्जर 49- हेमवती पुत्री मनभरी धर्मपत्नी ताराचन्द वल्द बदरी प्रसाद 50- पवित्रा पुत्री मनभरी धर्मपत्नी रतनलाल पुत्र बदरीप्रसाद निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ 51- भुराराम पुत्री इनावती धर्मपत्नी बालमुकन्द निवासी ग्राम फतेहपुरी दड़ौली जिला रेवाड़ी 52- बिमला देवी पुत्री इनावती पुत्री रामप्रसाद धर्मपत्नी ठाकरदत निवासी गढी बोलनी रोड नजदीक माडल टाउन रेवाड़ी 53- मांगेराम 54- राजकुमार 55- कसान पुत्रान भगवानी पुत्री रामप्रसाद धर्मपत्नी नेकीराम निवासीगण ढाणी साल्हावास तहसील मातनहेल जिला झज्जर 56-किताबो पुत्री भगवानी धर्मपत्नी महादेव 57-कृष्णा पुत्री भगवानी धर्मपत्नी टेकचन्द निवासीगण मौजा भगोत माजरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) 58- कमलेश पुत्री भगवानी धर्मपत्नी विजय सिंह पुत्र सुखलाल निवासी खण्डेवला तहसील पटौदी जिला गुरूग्राम 59- छैलती पुत्री रामप्रसाद विधवा बन्सीलाल निवासी मौजा फतेहपुरी दड़ौली जिला रेवाड़ी।
....फरीक दोयम
दरखास्त फकुल रहन अराजी जराई वाका रकबा मौजा सुर्खपुर तहसील कोसली जिला रेवाड़ी।
उपरोक्त केस मेरे न्यायालय सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी कोसली में विचाराधीन है। उक्त केस में प्रतिप्रार्थी को बजरिये पब्लिकेशन तलब किया जाता है। प्रतिप्रार्थी मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने केस की पैरवी दिनांक 03.12.2025 को कर सकते है। बाद गुजरने म्याद आप के खिलाफ नियम अनुसार एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। आज दिनांक 26/11/25 को मेरे न्यायालय की मोहर व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
एस०डी०एम०/कम कलैक्टर, कोसली

सूचना
सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्प्ले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

राशिफल

मेष रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा।

वृष परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। मानसिक शान्ति रहेगी,परन्तु बातचीत में संयत रहें। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मिथुन तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।सेहत का ध्यान रखें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

कर्क आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

सिंह कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

कन्या परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती हैं। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। क्रोध के अतिरेक से बचें।

तुला धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। चिकित्सीय खर्च बढ़ सकते हैं।

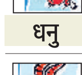
वृश्चिक भाग-दौड़ अधिक रहेगी। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। बातचीत में सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास करें। वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं।

धनु कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक या बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

मकर व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। सन्तान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

कुंभ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। पठन-पाठन में रुचि रहेगी। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि के स्रोत विकसित होंगे।

मीन दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। वाणी में मधुरता रहेगी।

सफीदों के खरक गागर निवासी युवक का शव डेढ़ महीने बाद इंग्लैंड से पहुंचा

जींद। सफीदों खंड के गांव खरक गागर गांव निवासी 26 वर्षीय कमल कुंडू का शव डेढ़ महीने बाद गांव पहुंच पाया। डेढ़ महीना पहले इंग्लैंड में अचानक मौत हो गई थी। कमल कुंडू कुछ समय पहले अवैध रूप से किसी तरह इंग्लैंड गया था। वहां वह काम करने लगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 16 अक्टूबर को अचानक कमल कुंडू का निधन हो गया। परिवार को सूचना पहुंची लेकिन परिवार का कोई सदस्य शव को इंग्लैंड जाकर वापस लाने की स्थिति में नहीं था। गांगोली निवासी सज्जन देशवाल को यह बात पता चली। वह इंगलैंड में रह रहे हैं तथा वहां पर हरियाणवी इन यूके संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं। वह कमल कुंडू के शव को भारत पहुंचाने में जुट गए। गांगोली तथा खरक गागर गांव आपस में गुहांड हैं। लगभग डेढ़ महीने बाद शुक्रवार को कमल कुंडू का शव गांव पहुंच पाया। शव को इंग्लैंड से गांव पहुंचाने पर जो लाखों रुपये खर्च हुए वह सज्जन देशवाल और उनके साथियों ने किए।

बुझ गया घर का इकलौता चिराग

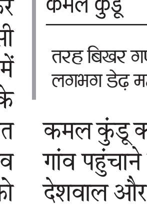

कमल कुंडू

अजमेर की बेटी सोनिया व अन्य परिजनों का डेढ़ महीने से रो-रोकर बुरा हाल था। कमल कुंडू पिता अजमेर का इकलौता बेटा था। कमल कुंडू को जब पिता अजमेर व परिवार के दूसरे लोगों ने इंग्लैंड भेजा थाए तब उन्होंने कमल और खुद अपने लिए कई तरह के सुनहरे सपने संजोए थे, जो इंग्लैंड में कमल की मौत के साथ तिनके की तरह बिखर गए। कमल की मौत की समाचार से परिवार पिछले लगभग डेढ़ महीने से भारी सदमे में था।

देश के 33 शहरों में एक साथ आयोजित होगी एक दिवसीय कम्यूनिटी डे मीटअप

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गुरुग्राम

पोकेमॉन गो कम्यूनिटी डे पर रविवार को पिकीपेक, वुडपेकर पोकेमॉन को विशेष रूप से फीचर किया जाएगा। यह एक दिवसीय कम्यूनिटी डे मीटअप दोपहर को एक साथ देश के 33 शहरों में आयोजित होगी। कम्यूनिटी डे मीटअप में नई दिल्ली के सेक्टर 6, द्वारका में प्लाज़ा पार्क, ईरोज़ वन मॉल, महाराजा अग्रसेन पार्क और लोधी गार्डन, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्वरूप जयंती पार्क, गुरुग्राम के लीज़र वैली पार्क, मुंबई के काला में हॉर्निमन सर्कल, आईआईटी बॉम्बे, वीर सावरकर उद्यान और शिवाजी पार्क (दादर), नवी मुंबई के वाशी में इनऑर्बिट मॉल, ऐरोली में राजीव गांधी गार्डन और कलांबोली के सेक्टर 10 में मंडावा गार्डन, पुणे के श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर, सरसबाग, फरीदाबाद के सेक्टर-12 में ताऊ देवीलाल पार्क, देहरादून के गांधी पार्क, गुवाहाटी के लतासिल प्लेग्राउंड, जयपुर के जवाहर सर्किल, भुवनेश्वर के खरवेला पार्क, बेंगलुरु के हनुमान पार्क, क्यूब्बन पार्क, श्रीमती लक्ष्मी देवी उद्यानवन, सेंट्रो मॉल और एचएसआर लेआउट में स्वाभिमान पार्क), कानपुर के मोतीझील में कारगिल पार्क, चंडीगढ़ के सेक्टर 16बी में रोज़ गार्डन, वडोदरा के सयाजी बाग में सेंट्रल पार्क शामिल हैं।

शब्द पहेली - 6063

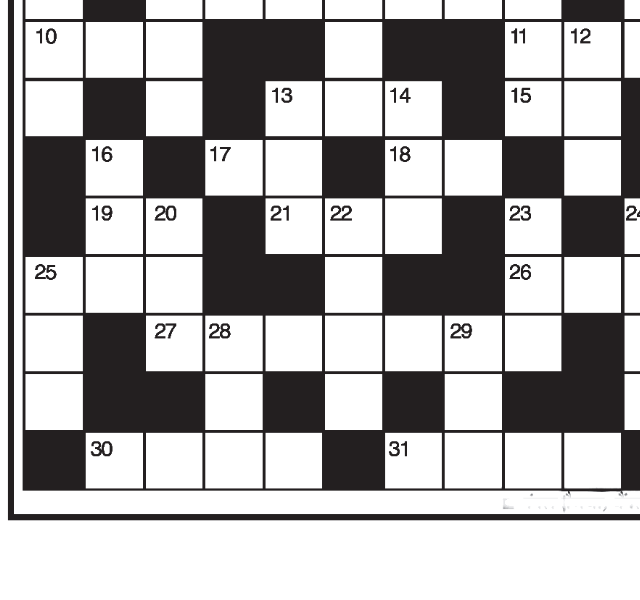

बाएँ से दाए
1. ईष्ट कृपा, वर-4
3. मान का विलोम-4
8. शैतानी करना-4,3
10. झगड़ा, बैर-3
11. जंगल, वन-3
13. सर्दी से बचने के लिये जलाई गई लकड़ियों का ढेर-3
15. जलने के बाद बचे अवशेष-2
17. कार्य-2
18. पतवार-2
19. नमाज से पहले हाथ-पांव धोना-2
21. नमस्कार-3
25. बूंद-3
26. जिज्ञासा, लगन-3
27. आत्मोत्सर्ग करना-4,3
30. मां के माता-पिता-2,2
31. रपटना-4

ऊपर से नीचे
2. वलय, घेरा-3
4. तीन घंटे का समय-3
5. खिसकना-4
6. उन्मादी, मदमस्त-4
7. यज्ञ, होम-3
8. नगर-3
9. तिरस्कृत-3
12. रूप अभिमान-3
13. शांति-3
14. प्रतिज्ञा-3
16. सहभोज-3
20. मोजा, पायताबा-3
22. उदारता-4
23. परवरिश करना-3
24. वचन तोड़ना-4
25. लेखनी-3
28. लिखावट-3
29. अमीर, धनवान-3

शब्द पहेली- 6062 का हल

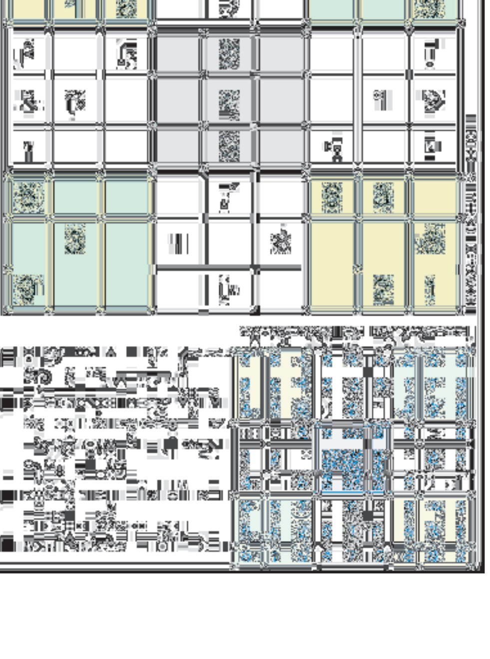

सेहत के लिए दी नसीहत

सीजेआई ने जजों के काम को बताया बेहद तनावपूर्ण, मनोरंजक कार्यक्रमों में शामिल हों

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि जजों को मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए ताकि वे खुद को रिचार्ज कर सकें। सीजेआई ने कहा कि जजों के काम के घंटे लंबे होते हैं और उनका काम बेहद तनावपूर्ण होता है। उनके काम की प्रकृति को देखते हुए उन्हें मनोरंजक गतिविधियां करनी चाहिए। मनोरंजक गतिविधियों में वे गतिविधियां शामिल की जाती हैं, जिन्हें लोग अपने शरीर और दिमाग को तरोताजा करने के लिए करते हैं। इनमें खेलकूद, योग-ध्यान, तैराकी या पैदल चलना आदि कुछ भी हो सकता है।

सीजेआई सूर्यकांत

सीजेआई ने ऑल इंडिया जज बैडमिंटन स्पर्धा के उद्घाटन में यह बात कही

त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई दो दिन की यह चैंपियनशिप

केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल और केंद्रीय मंत्री रिजिजू भी कार्यक्रम में मौजूद रहे

मनोरंजक गतिविधियों को आदत में शुमार करें

सीजेआई ने ऑल इंडिया जज बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जजों को अपनी उम्र के हिसाब से किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल होना चाहिए। सीजेआई ने कहा 'जजों के काम के घंटे ज्यादा हैं और उनका काम की प्रकृति भी तनावपूर्ण है। उन्हें कई घंटों तक बैठकर काम करना होता है। ऐसे में सभी जजों को मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए और इसे अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। जजों को रिचार्ज करने के लिए ये जरूरी है।

उच्च न्यायालयों के जज सेहत पर ध्यान दे रहे

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उच्च न्यायालयों के जज बड़ी संख्या में इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं, इससे पता चलता है कि वे अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह दो दिवसीय खेल आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित किया जा रहा है। समापन समारोह और इनाम वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अबंतिका डेका द्वारा किया जा रहा है।

आज होगा समापन और पुरस्कार वितरण

दो दिन की यह चैंपियनशिप यहां त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई है। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता रविवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ करेंगे।

खुद को रखें तरोताजा

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायाधीशों का काम घंटों लंबा होने के साथ-साथ अत्यंत तनावपूर्ण होता है, जिसके लिए उन्हें अवकाश के दौरान स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि न्यायधीशों को अपनी उम्र के हिसाब से मनोरंजन गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के काम के घंटे लंबे होते हैं और उनके काम का स्वरूप बहुत तनावपूर्ण होता है। सभी न्यायाधीशों को किसी मनोरंजक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए। उन्हें खुद को तरोताजा करने के लिए मनोरंजन की जरूरत होती है।

ब्रेकफास्ट पालिटिक्स के बाद बोले सिद्धारमैया और शिवकुमार

हम दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं और न कभी होंगे, आलाकमान की हर बात मानेंगे

एजेंसी ▶▶ बेंगलुरु

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उनके आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। इसके बाद दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि नाश्ता अच्छा था। हमने वहां किसी भी विषय पर बात नहीं की। हमने सिर्फ नाश्ता किया। डीकेएस हमारे घर आए। शिवकुमार ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे। हमारा एजेंडा 2028 के चुनाव हैं। स्थानीय निकाय चुनाव महत्वपूर्ण हैं। हमने उन पर चर्चा की। हमने 2028 के चुनावों में कांग्रेस को वापस लाने पर भी चर्चा की। हमने चर्चा की कि हम साथ चलेंगे। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे।

भाजपा बोली- तो अपना ब्रेकअप ठीक कर रहे थे

दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की

सिद्धारमैया बोले- नाश्ता अच्छा था

किसी भी विषय पर बात नहीं की

भाजपा और जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत

नाश्ते के बाद सिद्धारमैया और डीके ने की प्रेस कांफ्रेंस

अब कोई भ्रम नहीं रहेगा: सिद्धारमैया

शिवकुमार के साथ नाश्ते पर बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम आलाकमान की हर बात मानेंगे। अबसे कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी भी कोई भ्रम नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने भ्रम पैदा किया है।

सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा और जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है। दोनों ने बयान दिया है कि वे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उनके पास केवल 60 विधायक हैं और जेडीएस के पास 18 विधायक हैं। वे हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 140 विधायक हैं। यह एक निरर्थक कवायद है। हम उनके झूठे आरोपों का सामना करेंगे। जहां तक मुझे पता है, कुछ विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वे आलाकमान से मिलने गए होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नेतृत्व के खिलाफ हैं। उनमें से कुछ ने मुझसे बात की और बताया कि वे दिल्ली क्यों गए थे।

हम सुशासन प्रदान कर रहे: शिवकुमार

शिवकुमार ने कहा कि जहां तक नेतृत्व का सवाल है, यह पार्टी आलाकमान को तय करना है। वे जो भी कहेंगे, हम उसका पालन करेंगे। हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। पार्टी देश में एक कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम 2028 में अपनी जीत दोहराएंगे और मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। हम सुशासन प्रदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

जेडीएस ने भी किया बड़ा हमला

सिद्धारमैया-डीके बाज की तरह नजर रखकर अपना झुंड संभाल रहे

जनता दल (सेक्युलर) ने भी कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सिद्धारमैया और डीके

शिवकुमार सत्ता मजबूत करने व गुटबाजी संभालने में लगे हैं, जबकि राज्य के असली मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। सत्ता के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार विरोधी बने सहयोगी विधायकों को खिलाकर-पिलाकर और उन पर बाज की तरह नजर रखकर अपना झुंड संभाल रहे हैं।

हमें जो संदेश देना था दे दिया बोले शिवकुमार

दोनों ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस में दरार के विपक्ष के दावों को खारिज करने की कोशिश की। शिवकुमार ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में किसी भी बगावत की संभावना को खारिज किया। डीके ने कहा कि हमें जो भी संदेश देना था,मैंने कांग्रेस को दे दिया है।

ब्रेकफास्ट मीटिंग पर भाजपा का तंज

ब्रेकअप पर मेकअप हो रहा, एकता का नाटक हो रहा

सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच शनिवार को नाश्ते पर मुलाकात हुई।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे ब्रेकअप पर मेकअप वाली मीटिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपनी आंतरिक कलह को दबाने के लिए एकता का नाटक कर रहे हैं। ये नाश्ते पर बैठक नहीं थी।

राज्य की जनता मेन्यू में थी ही नहीं

पूनावाला ने कहा कि हमने इन दोनों नेताओं के बीच ट्विटर वॉर भी देखी है। दोनों बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड डिजर्व करते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है उस नाश्ते की टेबल पर कर्नाटक की जनता मेन्यू में थी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति थी, जनता की नहीं।

कबीर के बयान से बंगाल में घमासान

भले ही टीएमसी छोड़नी पड़े बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे

मैं किसी से नहीं डरता, 6 दिसंबर को नींव रखूंगा

टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर

एजेंसी ▶▶ मुर्शिदाबाद

पश्चिम बंगाल की भरतपुर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने यह ऐलान करके सियासी भूचाल ला दिया है कि वे 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देने और दिसंबर तक नई सेक्युलर पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। कबीर ने कहा कि मैं टीएमसी छोड़ दूंगा, लेकिन मस्जिद बनाऊंगा। मुस्लिम लोगों की मदद से, सरकार से नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी से फाइनेंशियल मदद लेकर मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा।

एक कट्ठा जमीन पर नींव रखी जाएगी

कबीर ने दावा किया कि 2011 के सेंसस के मुताबिक 33 पर्सेंट मुस्लिम थे। अब बंगाल में 38 पर्सेंट मुस्लिम हैं। 4 साल इंतजार करो और यह 40 पर्सेंट हो जाएगा। किसी भी कीमत पर 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव तैयार हो जाएगी। शुरुआत में एक कट्ठा जमीन पर नींव रखी जाएगी।

ममता दुर्गा पूजा कार्निवल कर रहीं तो मस्जित गलत कैसे?

कबीर ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि ममता बेनर्जी दीघा में जगन्नाथ मंदिर बना रही हैं, सड़कें ब्लॉक करके दुर्गा पूजा कार्निवल कर रही हैं। अगर मैं मस्जिद बनाने जाऊं तो यह क्राइम हो जाता है? मैं उनसे क्या बात करूं? अगर कोई मुझे धमकी देता है तो क्या मैं उसे मिठाई भेजूंगा? मस्जिद प्राथमिकता है। नमाज पढ़ना मुसलमानों का फर्ज है। मुसलमानों को मंदिर बनाने पर कोई एतराज नहीं है, तो मस्जिद बनाने पर एतराज क्यों?

सपा मुखिया अखिलेश ने भरा 'सर' फार्म

लखनऊ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी 'सर' फार्म भर दिया है। बताया गया कि उन्होंने 27 नवंबर को फार्म भरा है। शनिवार को भी प्रेस वार्ता करके उन्होंने प्रदेश में हो रही बीएलओ की मौतों पर भाजपा को निशाने पर लिया। अखिलेश ने इस दौरान सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि एसआईआर, भाजपा और आयोग की मिलीभगत की साजिश है।

रक्षित ने लौटाया सगाई का 21 लाख का चेक

वाजिदपुर। यहां स्थित द ग्रांड पैलेस रिसोर्ट में हुई रक्षित राणा और दिव्या की सगाई में एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। रक्षित ने 21 लाख का चेक ससम्मान लौटाकर संदेश दिया कि दहेज अभिशाप है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है। किसी भी राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इंडी ब्लाक में टूट की अटकलें हो गई शुरू

कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आरजेडी से गठबंधन को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया

कांग्रेस आलाकमान से राजद से गठबंधन तोड़ने की वकालत की

एजेंसी ▶▶ पटना

बिहार के नेता उठाने लगे महागठबंधन पर सवाल

बिहार विधानसभा चुनावमें करारी हार झेलने के बाद महागठबंधन में टूट की अटकलें हैं। समीक्षा के दौरान कांग्रेस के अधिकतर उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से गठबंधन को चुनावी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। कई ने तो कांग्रेस आलाकमान को राजद से गठबंधन तोड़ने की वकालत भी कर दी। इसके बाद से सियासी पारा गरम है। हालांकि, पार्टी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से गठबंधन के भविष्य को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है।

खरगे और राहुल ने की थी बात

खरगे और राहुल आपस में बात करते हुए

नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस ने बिहार चुनाव की हार की समीक्षा प्रदेश स्तर के नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भीबैठक में मौजूद थे।

अकेल लड़ते तो बेहतर परिणाम होते

अधिकतर उम्मीदवारों ने आलाकमान को बताया कि राजद से गठबंधन की वजह से कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। अगर कांग्रेस इस चुनाव में अकेले मैदान में उतरती तो परिणाम बेहतर होते।

गठबंधन में किसी को पकड़कर नहीं रखा: राजद

राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि गठबंधन में किसी को पकड़कर रखा नहीं जा सकता है। कांग्रेस की अगर मर्जी है कि अकेले और अलग चलेंगे, तो क्या कर सकते हैं। अगर कांग्रेस को लगता है कि गठबंधन में रहने पर हार हुई है और अलग होना है तो अच्छी बात है।

एनएचआरसी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा

बसों में अलग ड्राइवर कैबिन गलत व अधिकारों का उल्लंघन

बस डिज़ाइन को लेकर सभी राज्यों से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सार्वजनिक परिवहन बसों की असुरक्षित डिजाइन पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने कहा कि कई बसों में ड्राइवर केबिन को पूरी तरह अलग बनाया जा रहा है, जिससे आग लगने या आपात स्थिति में ड्राइवर और यात्रियों के बीच समय पर संवाद नहीं हो पाता। यह यात्रियों की जान के लिए बड़ा खतरा और जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। सभी मुख्य सचिव सीआईआरटी की सभी सिफारिशों को राज्यभर में लागू करें। लापरवाहों पर तत्काल कार्रवाई हो। पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा व सहायता दी जाए। 2 सप्ताह के भीतर एटीआर भेजें।

पीड़ित परिवारों को मुआवजा व सहायता दें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

आग की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया

हाल में कई बसों में सफर के दौरान आग की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। आयोग की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया और परिवहन मंत्रालय व केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान पुणे से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी।

सीआईआरटी जांच में गंभीर खामियां मिलीं

सीआईआरटी ने बताया कि राजस्थान परिवहन विभाग के अनुरोध पर जांच में हादसे वाली बस में कई गंभीर कमियां मिलीं। बस बॉडी निर्माण में मानकों का उल्लंघन किया गया था। स्लीपर बसों में ड्राइवर पार्टिशन डोर नियमों के खिलाफ है, फिर भी लगाया गया था। 12 मीटर से लंबी बसों में 5 आपात निकास अनिवार्य हैं पर उपलब्ध नहीं थे।

बस में एफडीएसएस और मानक उपकरण नहीं मिले

अनिवार्य फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम बस में मौजूद नहीं था। स्लीपर कोच के स्लाइडर-चेसिस एक्सटेंशन जैसे खतरनाक हिस्से बगैर अनुमति लगाए गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान का कहना है कि सभी स्लीपर कोचों में ड्राइवर पार्टिशन हटाया जाए, एफडीएसएस अनिवार्य रूप से लगाया जाए, 10 किलो के फायर एक्सटिंग्विशर चेक किए जाएं और नियमों के उल्लंघन वाले सभी बस बॉडी डिजाइन तत्काल बंद किए जाएं।

भारत में चार नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन चार संहिताओं में 'कोड ऑन वेजेज 2019', 'इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020', 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020' और 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020' शामिल हैं। श्रम सुधारों का यह नया ढांचा भारत के आर्थिक, डिजिटल और औद्योगिक भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मॉडल है। यह सुधार न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान है बल्कि आने वाले दशकों में रोजगार परिदृश्य को स्थिरता, पारदर्शिता और सशक्तिकरण की नई दिशा देगा। नए कानूनों के लागू हो जाने से भारतवर्ष की उत्पादन क्षमता, रोजगार गुणवत्ता, औद्योगिक सामंजस्य और वैश्विक स्पर्धा में वृद्धि की पूर्ण संभावना दिखाई पड़ रही है। कह सकते हैं कि देश ने अपनी श्रम नियमावली को फिर से लिखा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत आधार प्रदान करने में नए चार श्रम कोड कारगर भूमिका अदा करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगर नए कानून जमीन पर उतरने में सफल रहे तो श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इसी का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

नए श्रम कानूनों से बदलेगी तस्वीर

विश्लेषण
रोहित माहेश्वरी
स्वतंत्र पत्रकार

सालों से इंतजार किए जा रहे चार नए श्रम कानूनों को बीती 21 नवंबर को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन चार संहिताओं में 'कोड ऑन वेजेज 2019', 'इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020', 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020' और 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020' शामिल हैं। 29 श्रम कानूनों को खत्म करके चार नए कानून पेश किए गए हैं, जो सभी तरह के कर्मचारियों को कवर करते हैं। इस कानून के तहत सैलरी, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेच्युटी और समान काम की समान सैलरी आदि जैसे बदलाव हुए हैं। इसमें दो राय नहीं कि नए श्रम कानून लागू करना देश के श्रम परिदृश्य में एक नए दौर में प्रवेश करने जैसा है। केंद्र सरकार ने चारों श्रम कानून मसलन वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्य स्थितियों को अधिसूचित किया है। दावा किया जा रहा है कि इससे अनुपालन सरल बनेगा, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होगा और ये कदम श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूती देगा। केंद्र सरकार की इस कदम से कर्मचारियों को समय पर वेतन, औपचारिक नियुक्ति पत्र देने, न्यूनतम वेतन की गारंटी और वार्षिक स्वास्थ्य जांच का वादा किया गया है।

इसमें दो राय नहीं कि नए श्रम कानून लागू करना देश के श्रम परिदृश्य में एक नए दौर में प्रवेश करने जैसा है। केंद्र सरकार ने चारों श्रम कानून मसलन वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्य स्थितियों को अधिसूचित किया है। दावा किया जा रहा है कि ये कदम श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूती देगा। निस्संदेह, देश ने अपनी श्रम नियमावली को फिर से लिखा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। अगर नए कानून जमीन पर उतरने में सफल रहे तो श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।

सैलरी का दायरा बढ़ेगा

नए कानूनों के तहत कर्मचारियों को समय पर सैलरी दी जाएगी। देशभर में मिनिमम सैलरी का दायरा बढ़ेगा यानी कि बाकी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि कोई भी सैलरी इतनी कम नहीं हो कि कर्मचारियों का जीवन-यापन कठिन हो। नए कानून के तहत अब ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि 1 साल की सर्विस पर ही ग्रेच्युटी दी जाएगी। यह ग्रेच्युटी फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिलेगी। इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर ही सभी फायदे जैसे छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएंगी। नए कानून के तहत एक और बड़ा बदलाव यह है कि

सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने का किया गया है। इसके अलावा गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स ओर एग्रीगेटर्स को इन कानूनों के तहत पहली बार डिफाइन किया गया है। इन्हें भी आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से वेलफेयर बेनिफिट्स दिया जाएगा, जिसमें पीएफ से लेकर पेंशन तक का लाभ शामिल होगा। 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। केंद्र सरकार मजदूरों की बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानदंड बनाएगी।

महिला कर्मियों का हित

नए कानूनों के तहत महिलाएं सभी जगहों पर काम कर सकती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग, भारी मशीनरी और खतरनाक काम शामिल हैं, जिससे सभी के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित होंगे। हर साइट पर ऑन-साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए जरूरी सेफ्टी कमेटी और खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग पक्का करना है। वहीं फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (एफटीई) से रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा, स्थायी कर्मचारी के बराबर फायदे जैसे कानूनी सुरक्षा पक्की होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर नकार दिया गया है। महिला हो या पुरुष समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने का अधिकार होगा। सभी कामगारों के लिए मिनिमम सैलरी की गारंटी होगी। सभी तरह के कर्मचारियों को ऑफर लेटर देना होगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा, रोजगार विवरण और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। छुट्टी के दौरान मजदूरी देना अनिवार्य किया गया है। मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से तय की गई फ्लोर वेज के हिसाब से वेतन दिया जाएगा।

ग्रेच्युटी व प्रोविडेंट फंड बेहतर

सभी प्रवासी कामगारों (डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर-बेस्ड और खुद माइग्रेटेड) को बराबर वेतन, वेलफेयर बेनिफिट और पीडीएस पोर्टेबिलिटी का लाभ दिया जाएगा। कामगार 3 साल तक लंबित बकाय के निपटारे के लिए दावा कर सकते हैं। सभी डॉक वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा के लाभ तय कर दिया गया है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या अस्थायी कर्मचारी। जानकारों के मुताबिक नए लेबर कोड्स 'कोड ऑन वेजेज' और 'सोशल सिक्योरिटी' के तहत 'वेजेज' (सैलरी) की परिभाषा को एक जैसा बनाते हैं। इससे ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड बेहतर होगा, लेकिन अगर कंपनियां खर्च कम करने के लिए अलाउंस घटाती हैं, तो हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है। श्रम क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, अब 'वेजेज' में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस यानी आरए शामिल होंगे। कुल कमाई का 50 प्रतिशत (या सरकार द्वारा तय की गई कोई और प्रतिशत राशि) 'वेजेज' में जोड़ा जाएगा। इससे ग्रेच्युटी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना में एकरूपता आएगी। पहले कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखकर बाकी पैसा अलग-अलग भत्तों के रूप में दे देती थीं। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी में उनका योगदान कम होता था। लेकिन अब सरकार ने नियम बना दिया है कि आपकी कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम आधा हिस्सा बेसिक सैलरी होना चाहिए। इससे आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स तो बढ़ेंगी, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाले पैसे थोड़े कम हो सकते हैं। यह एक तरह से आपकी भविष्य की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम है, भले ही अभी थोड़ा जेब पर भारी पड़े। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्रम सुधारों के कई प्रावधान, लंबे समय से अपेक्षित प्रगति का संकेत देते हैं।

जमीनी स्तर पर हो बदलाव

सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिक वैधानिक अधिकार, अनिवार्य लिखित नौकरी अनुबंध, निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिये बेहतर ग्रेच्युटी तक पहुंच और स्वास्थ्य व सुरक्षा पर स्पष्ट मानदंड, औपचारिक प्रावधानों और पारदर्शिता की दिशा में बदलाव को रेखांकित करते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक-सुरक्षा ढांचे के भीतर गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता देना शायद सबसे बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन माना जा सकता है। निश्चय ही, ये देश के लाखों कामगारों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। निस्संदेह, देश ने अपनी श्रम नियमावली को फिर से लिखा है। लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। अगर नए कानून जमीन पर उतरने में सफल रहे तो श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।

नए श्रम कानून : श्रमिक जीवन का नया सूर्योदय

उम्मीद
डॉ.सूर्यकांत मिश्रा
स्वतंत्र पत्रकार

श्रमिक कल्याण की प्रतिबद्धता से जुड़े नए श्रम कानून के लागू हो जाने के बाद से शोषण की कूटनीति को समाप्त करने का मार्ग खोला जा सकेगा। पुराने कानूनों में राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए किए जाने वाले घेराव के साथ तालाबंदी जैसी औद्योगिक गतिविधियों को भी रोका जा सकेगा। 'श्रमेव जयते' जैसे सार्थक शब्द का आह्वान श्रम के क्षेत्र में विकास यात्रा के मार्ग को सुगम बनाते हुए श्रम की गरिमा और श्रमिकों के सम्मान का प्रतीक बनकर जरूर उभरेगा। आजाद हिंदुस्तान में अब तक जो श्रम कानून चल रहे थे, वे आजादी से पूर्व 1920 और आजादी के तुरंत बाद 1950 में लागू किए गए थे । कहीं न कहीं अंग्रेजों की सोच कानून में घुली हुई थी। 105 वर्षों की लंबी यात्रा में समय-काल-परिवर्तन के अनुसार युगकालीन परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। तब समय की जरूरत के हिसाब से कानून में परिवर्तन करना एक अच्छी सोच कही जा सकती है। अलग-अलग टुकड़ों में बंटे 29 श्रम कानूनों को चार मुख्य कोड में समेटना कहीं न कहीं पेचीदे कानून को सरल बनाने की दिशा में एक अच्छा निर्णय माना जाना चाहिए। वर्तमान केंद्रीय सरकार की यह सोच कि निजी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सम्मानित जीवन मिले। अनुकूल कार्य क्षेत्र की प्राप्ति हो। समान वेतन का हक मिले, निम्न तबके को कल्याणकारी योजना की ओर अग्रसर करता है। नए श्रम कानून का सबसे ज्यादा लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। इन कानूनों के चलते अब जहां शोषण से मुक्ति मिलेगी, वहीं वेतन की नियमितता श्रमिकों को खुशियों का उपहार देती दिखेगी। नए नियमों के अनुसार अब नियोक्ता को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा। सबसे बड़ा लाभ सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्यूटी के रूप में होगा। पुराने कानून जहां कम से कम पांच वर्ष के सेवाकाल के बाद ही ग्रेच्युटी भुगतान की जंजीरों में जकड़ दिए गए थे , वहीं अब नए कानून के तहत हर वह कर्मचारी जिसने एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है , ग्रेच्यूटी का हकदार होगा। हमारा पुराना श्रम कानून जहां महिला और पुरुषों के वेतन की विसंगति से जूझ रहा था , अब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वेतन का अधिकार प्रदान कर रहा है । सीधे शब्दों में कहा जाए तो जेंडर आधारित भेदभाव को नए कानून ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। चार नए श्रम कोड के चलते प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन सम्मानित और सुनियोजित तरीके से सांस ले पाएगा।

नए श्रम कानून का सबसे ज्यादा लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने जा रहा है । इनके चलते अब जहां शोषण से मुक्ति मिलेगी । वहीं वेतन की नियमितता श्रमिकों को खुशियों का उपहार देती दिखेगी।

नए कानून को कार्यरूप देने के पीछे जो उद्देश्य नजर आ रहे हैं, वे कर्मचारियों को लाभान्वित करने के साथ ही कार्यक्षेत्र में किए जाने वाले शोषण को समाप्त करने वाले हैं। साथ ही इन कानूनों में सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा नियोक्ताओं को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने वाला होगा। आत्मनिर्भर भारतवर्ष के स्वप्न को साकार करने के लिए ही शायद सरकार के द्वारा 29 श्रम कानूनों को चार कानून में समेटा गया है। देश में 2025 नवंबर माह के तीसरे सप्ताह से प्रभावशील चार श्रम कानून कोड वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तथा ओएसएच और कार्य शर्तें संहिता के रूप में लागू किए जा चुके हैं। जैसा कि वेतन संहिता के नाम से ही विदित होता है कि यह कोड कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ समय पर वेतन देने की मजबूत व्यवस्था के लिए बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद सम्मानित जीवन यापन के क्षेत्र में पीएफ , ईएसआईसी , ग्रेच्यूटी और बीमा जैसे लाभों का आवरण प्रदान करेगी । इसी तरह औद्योगिक संबंध संहिता कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी अनावश्यक छंटनी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाली होगी । सबसे अहम चौथे कोड में काम के दौरान सुरक्षा और कार्यक्षेत्र को अनुकूल वातावरण प्रदान करने से संबंधित नियमों से बंधा होगा। संक्षिप्त में कहें तो नए कानूनों के जरिए सरकार ने कानून के सरलीकरण का शानदार प्रयास किया है। इन कानूनों के तहत गिग वर्कर अर्थात ऐसे कर्मचारी जो स्थाई नहीं हैं , बल्कि अस्थाई रूप से काम पर रखे जाते हैं , उन्हें भी कानून के दायरे में लाया गया है । नए कानूनों के लागू हो जाने से भारतवर्ष की उत्पादन क्षमता, रोजगार गुणवत्ता, औद्योगिक सामंजस्य और वैश्विक स्पर्धा में वृद्धि की पूर्ण संभावना दिखाई पड़ रही है। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत आधार प्रदान करने में नए चार श्रम कोड कारगर भूमिका अदा करेंगे।

श्रम संसार की तस्वीर बदलने वाली गारंटी

राष्ट्र-चिंतन
आचार्य श्रीहरि
स्वतंत्र पत्रकार

श्रमेव जयते। श्रम की प्रधानता और समृद्धि के बिना जीवंत राष्ट्र की परिकल्पना नहीं हो सकती है। श्रम की कसौटी पर निर्माण और विकास की परिकल्पना बनती है। इसलिए श्रम की महत्ता और अनिवार्यता को अस्वीकार करना मुश्किल है। इनकी उपेक्षा और इन पर उदासीनता अस्वीकार है। सरकार की ही नहीं, बल्कि नियोक्ता और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी भी स्वस्थ और समृद्ध श्रम संसाद की बनती है। यह अच्छी और स्वागतपूर्ण कदम है कि नरेन्द्र मोदी ने मजदूरों की तस्वीर बदलने की गारंटी दी है, उनकी आजीविका के अधिकार को सशक्त बनाया है। उनके होने वाले शोषण और उत्पीड़न पर रोक लगाने की व्यवस्था की है और भेदभाव की नीतियों को समाप्त करने की घोषणा की है, यानी कि श्रमेव जयते। इस निमित नरेन्द्र मोदी की सरकार ने चार नए श्रम संहिताओं की घोषणा की है। इन श्रम संहिताओं की घोषणा से लगभग 30 साल के श्रम काले कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, जो काफी समय से प्रस्तावित और प्रत्याशित थे। चार नये श्रम संहिताओं को इस प्रकार से जानिये। पहला वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेल्फी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 में परिवर्तन कर दिया गया है। इससे मजदूरों के वेतन और सुरक्षा अधिकारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा और लाभकारी भी होगा। नए श्रम संहिताओं में मजदूरों के सभी प्रकार के अधिकारों और कल्याण की भावनाओं को निहित किया गया है। औद्योगिकीकरण और कारपोरेटिवकरण तथा रोजगार और श्रम के नये आयामों के उदभव और विकास के कारण मजदूरों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गयी थी, निवेशकों के सामने भी बहुत बडी समस्या थी, पूर्व की श्रम संहिताएं अस्पष्ट थी और विसंगतियों से भरी पड़ी थी, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच अविश्वास उत्पन्न करती थी, अधिकारों को लेकर संहिताएं स्पष्ट भी नहीं थी। न्यूनतम वेतनमान में हीलाहवाली थी, असमानता थी और शोषण युक्त था। नयी आर्थिक नीतियों के लागू होने से सर्वाधिक शोषण के शिकार मजदूर थे और उनके हित हाशिये पर थे, उनके आंदोलन करने के अधिकार और कर्तव्य पर नियोक्ता, पुलिस और प्रशासन की टेढी नजर रहने लगी थी। भारत की ये श्रम संहिताएं विश्व की अन्य संहिताओं के अनुपात में कितनी लाभकारी हैं, कितनी सहयोगी हैं और कितनी कल्याणकारी हैं? नई श्रमिक संहिताएं श्रमिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए बेमिसाल तो हैं पर नियोक्ताओं और सेवादाता कंपनियों के बीच भी श्रम कानूनों को लेकर विश्वास उत्पन्न करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि नरेन्द्र मोदी सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विश्वास और संतुलन बनाने की भूमिका निभाएगी।

इन श्रम संहिताओं की घोषणा से लगभग 30 साल के श्रम काले कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, जो काफी समय से प्रस्तावित और प्रत्याशित थे।

भारत में नए लेबर कोड : श्रमिक अधिकारों का नया अध्याय

रणनीति
सुनील कुमार महला
स्वतंत्र पत्रकार

केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 शुक्रवार को कार्य परिस्थितियों में बड़े बदलाव का कदम उठाते हुए देश में नई श्रम संहिता (लेबर कोड) लागू कर दी। यह वाकई काबिले-तारीफ है कि निजी एवं असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों के लिए उपयोगी इस नए लेवर कोड में अनिवार्य नियुक्ति-पत्र, न्यूनतम और समय पर वेतन की गारंटी और एक साल में ही ग्रेच्युटी भुगतान की व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ईएसआइसी सुविधा और 40 साल की सेवा के बाद अनिवार्य स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बता दें कि ईएसआईसी भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व और रोजगार से जुड़ी अन्य आपात स्थितियों में आर्थिक तथा चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद इसे सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कृषकों को मजबूत बनाने वाला है। इनसे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होगा, जो भविष्य में कामगारों के हकों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा, साथ ही विकसित भारत की यात्रा को भी तेज गति मिलेगी।' कितनी अच्छी बात है कि नए लेबर कोड में महिलाओं के लिए खास सुविधाएं जोड़ी गई हैं, वहीं खतरनाक व जोखिम वाले उद्योगों, गिग वर्कर्स और आइटी क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। आज के समय में ओला-उबर के ड्राइवर, स्विगी-जोमैटो, ब्लिंकिट ,अमेज़न के डिलीवरी पार्टनर, फ्रीलांसर (कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटर आदि), डिज़ाइनर, या अर्बन कंपनी जैसी सर्विस देने वाले लोग गिग वर्कर्स के रूप में जाने जाते हैं। यह काम लचीला होता है, इसलिए लोग अपनी सुविधा अनुसार समय

यदि पारदर्शिता से काम हो तो यह कोड अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

तय कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें स्थायी नौकरी जैसे लाभ जैसे पीएफ, पेंशन, मेडिकल सुरक्षा अक्सर नहीं मिलते। यही कारण है कि गिग वर्कर्स को असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है।

सच तो यह है कि गिग वर्कर्स, खनन श्रमिकों और टैक्सटाइल श्रमिकों के लिए नए लेबर कोड में विशेष इंतज़ाम किए गए हैं,जो सराहनीय हैं। वास्तव में अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआइसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे। इतना ही नहीं, खनन श्रमिकों के क्रम में आवागमन दुर्घटना पर मुआवजा, खान में सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों का ध्यान, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही साथ काम के घंटों की सीमा प्रतिदिन 8 से 12 घंटे, तथा प्रति सप्ताह 48 घंटे तय की गई है। टैक्सटाइल श्रमिकों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मसलन, ठेकेदार कर्मियों को समान वेतन, कल्याणकारी लाभ, बकाया निपटान के लिए तीन साल की अवधि, तथा ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान जैसी व्यवस्थाएं नये लेबर कोड में की गईं हैं। नए लेबर कोड में महिलाओं के लिए खास सुविधाओं में क्रमशः लिंग भेद निषेध, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं को सहमति व जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में तथा सभी प्रकार के काम की अनुमति, शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी, महिला कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में सास-ससुर को शामिल करना, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, क्रैच व वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के साथ ही साथ 3500 रुपये का मेडिकल बोनस दिए जाने की व्यवस्थाएं भी की गईं हैं। वास्तव में लेबर कोड में विभिन्न सुधारों से कामगारों को निश्चित ही लाभ हो सकेगा। कुल मिलाकर, श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नए लेबर कोड की आवश्यकता महसूस की गई। अब नए लेबर कोड से श्रमिकों के दिन बदलेंगे। हालांकि, इनकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि सरकार और उद्योग पारदर्शिता से काम करें तो यह कोड भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रोजगार, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक पहल

श्रम कानून
रवि शंकर
वरिष्ठ पत्रकार

एक लंबे इंतजार के बाद देश के श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, जो कई तरह से ऐतिहासिक है। इसकी मांग दशकों से की जा रही थी। पुराने 29 श्रम कानूनों को अब इतिहास बनाते हुए उनकी जगह 21 नवंबर से देश में चार नए श्रम कोड लागू हो गए हैं। इसे श्रम सुधारों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

ये कोड हैं- वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति संहिता 2020। इनका मकसद कामगारों को सुरक्षित काम, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा देना है। संसद ने ये चार लेबर कोड लगभग पांच साल पहले पारित कर दिए थे। लेकिन इन्हें अब जाकर लागू किया गया है। अब पूरे देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रम कानून एक जैसे होंगे। इन संहिताओं का सबसे बड़ा उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण को मजबूत बनाना, उद्योगों को सुगम कार्य-परिस्थिति देना, डिजिटल कार्य संस्कृति को औपचारिक मान्यता देना और गिग-प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे उभरते श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इससे भारत की उत्पादन क्षमता, रोजगार गुणवत्ता, औद्योगिक सामंजस्य और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। बहरहाल, इन कानूनों को लागू करते हुए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ऐसा मानना है कि ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए श्रम कानूनों से देश के करीब 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलेगी।

पहले देश में लागू श्रम कानून 1930-1950 के बीच के बनाए गए थे। उन कानूनों में श्रमिकों के आर्थिक हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन नए कानून इन बातों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि, कई मजदूर संगठनों का आरोप है कि ये कोड कंपनी मालिकों को पहले से कहीं अधिक अधिकार देते हैं। खासकर छोटी और असंगठित कंपनियों में कामगारों का शोषण बढ़ेगा। दावा किया जा रहा है कि यह अद्भुत संतुलन वाला कानून है, जिससे मजदूरों और कर्मचारियों को भी फायदा होगा तो उद्योग समूहों को भी लाभ होगा। सवाल है कि जब दोनों के लिए फायदे वाला कानून है तो इसे लागू करने में सरकार को छह साल क्यों लग गए? दूसरा सवाल यह है कि अगर ये कानून मजदूरों के हित में हैं तो देश के ज्यादातर बड़े मजदूर संगठन

वास्तव में श्रम कानून का कितना लाभ मिलता है यह इन कानूनों के अनुपालन के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है कि मजदूरों के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सीमित कर दिया गया है।

इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में संसद में पास करने से लेकर इनके नियम बना कर इन्हें लागू करने तक जब भी इन कानूनों की बात होती है तो दावा किया जाता है कि इनसे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलेगी, समय पर उचित वेतन मिलेगा तो दूसरी ओर कंपनियों को एक ऐसा सरल ढांचा मिलेगा, जिसके अनुपालन में उनको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यह सिर्फ सदिच्छा है। वास्तव में इसका कितना लाभ मिलता है यह इन कानूनों के अनुपालन के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि मजदूरों के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। नए कानून में प्रावधान है कि हड़ताल से 60 दिन यानी दो महीने पहले नोटिस देना होगा।

अगर कर्मचारी या मजदूर अपनी किसी समस्या के लिए तत्काल विरोध प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर पाएंगे तो उनकी समस्या को निराकरण कैसे होगा? वहीं सामाजिक सुरक्षा वाले तीसरे कानून में गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड की बात कही गई है। लेकिन यह फंड कैसे बनेगा? कंपनियां कितना योगदान करेंगी और मजदूरों को उसका लाभ कैसे मिलेगा, इस बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा वाले चौथे कानून में रोज के काम के घंटे का विस्तार 12 घंटे तक कर दिया है। असल में नए श्रम कानून जैसा कि हमेशा होता है उद्योग समूहों और निवेशकों के हितों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना और उद्योग समूहों का विस्तार करना है। सभी सरकारें मानती रही हैं कि उद्योगों का विकास होगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और संपन्नता आएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर कानून शोषण और गैर बराबरी को बढ़ाता है। ये कानून भी अपवाद नहीं हैं। इनमें भी फिक्स्ड टर्म नौकरी पर जोर दिया गया है, जिसका मतलब है कि स्थायी नौकरियां कम होंगी और ठेके पर काम ज्यादा उपलब्ध होगा। इससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी नहीं कम होगी। इसी तरह कंपनियां नियमों का कैसे अनुपालन करती हैं उसकी जांच और निगरानी की व्यवस्था कमजोर कर दी गई है। कुछ पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो नई श्रम संहिताएं आवश्यक संतुलन साधने में सफल दिखती हैं। ये बदलाव सिर्फ आज के कामगारों के लिए नहीं, आने वाले समय में काम की दुनिया बदलने की चुनौती के लिए हैं। दरअसल, श्रम सुधारों का यह नया ढ़ांचा भारत के आर्थिक, डिजिटल और औद्योगिक भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मॉडल है। यह सुधार न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान है बल्कि आने वाले दशकों में रोजगार परिदृश्य को स्थिरता, पारदर्शिता और सशक्तिकरण की नई दिशा देगा।

वुमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी, 2 शहर में 22 मुकाबले, मुंबई इंडियंस-आरसीबी के बीच पहला मैच

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 की शुरुआत 9 जनवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) और 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच मुकाबले के साथ होगी। डब्ल्यूपीएल 2026 के शेड्यूल की जानकारी देते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि नवी मुंबई में दो डबल-हेडर मुकाबले होंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में आयोजित होगा। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में 9-17 जनवरी के बीच मुकाबले नवी मुंबई में खेले जाएंगे। इस दौरान 11 मुकाबले आयोजित होंगे। इसके बाद शेष 11 मैच वडोदरा में होंगे। इनमें प्लेऑफ भी शामिल हैं।

वडोदरा लेग की शुरुआत गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले के साथ होगी। मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर इस सीजन में उतर रही है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस खिताब को जीतने वाली दूसरी टीम है। गुजरात जायंट्स वडोदरा लेग की शुरुआत आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से करेगी, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच 2025 के फाइनल का री-मैच होगा। 1 फरवरी को लीग स्टेज खत्म होने के बाद, एलिमिनेटर में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें हिस्सा लेंगी। टेबल टॉपर सीधे 5 फरवरी को फाइनल में पहुंचेगी।

टाइम टेबल

नवी मुंबई लेग:

- 9 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- 10 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम गुजरात जायंट्स
- 10 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स
- 11 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स
- 12 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स
- 13 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स
- 14 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
- 15 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स
- 16 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स
- 17 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस
- 17 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

वडोदरा लेग:

- 19 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- 20 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस
- 22 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स
- 24 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स
- 26 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस
- 27 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
- 29 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- 30 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस
- 1 फरवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स
- 3 फरवरी: एलिमिनेटर
- 5 फरवरी: फाइनल

खबर संक्षेप

ओजस्विनी ने जीती डीजीसी लेडीज एमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप

नई दिल्ली। ओजस्विनी सारस्वत ने दिल्ली गोल्फ क्लब में 222 के कुल स्कोर के साथ 15वीं डीजीसी लेडीज एमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में 115 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सारस्वत ने 222 अंकों के साथ ट्रॉफी जीती, जबकि केया बड्गु (225) दूसरे और योग्या भल्ला (232) तीसरे स्थान पर रही।

शीर्ष 10 में जगह बनाने के करीब अदिति अवनि शीर्ष 20 में बनाई जगह

मलागा। गोल्फर अदिति अशोक एंडालुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन डी एस्पाना में दूसरे राउंड के बाद शीर्ष 10 में जगह बनाने के करीब पहुंच गई जबकि अवनि प्रशांत ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 20 में जगह बना ली। इस प्रतियोगिता की पूर्व विजेता अदिति ने दूसरे राउंड में दो अंडर 70 का स्कोर बनाया और अब वह पांच अंडर 139 के साथ संयुक्त 11वें स्थान पर पहुंच गई है। अवनि ने दूसरे राउंड में तीन अंडर 69 का सर्वश्रेष्ठ कार्ड हासिल किया, जिससे उनका स्कोर चार अंडर हो गया और वह संयुक्त 17वें स्थान पर हैं।

गिल और अय्यर इंजरी के कारण बाहर, मैच दोपहर 1.30 से शुरू

आज से भारत-द.अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज, रोहित और कोहली की कड़ी परीक्षा

एजेंसी ▶▶| रांची

अब केवल वनडे में खेल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार से शुरू होने वाली तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में आकर्षण का केंद्र होंगे, जिससे वह 2026 में होने वाले विश्व कप के लिए अपना दावा भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम प्रबंधन इस श्रृंखला से चयन संबंधी समस्याओं का समाधान भी करना चाहेगा। उसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल में समाप्त हुई टेस्ट श्रृंखला के दौरान चयन संबंधी मसलों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा था। रोहित और कोहली दोनों अब केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय प्रारुप में खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के टेस्ट सीरीज हराने के बाद रोहित और कोहली की वनडे सीरीज जीतने के लिए कड़ी परीक्षा होगी। वहीं शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों इंजरी के कारण बाहर हैं।

केएल राहुल को कप्तानी की कमान

इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तान केएल राहुल के हाथों में सौंपी गई है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों इंजरी के कारण बाहर हैं।

बुमराह और सिराज को आराम

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है, जबकि नियमित कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोटिल हैं। उनकी अनुपस्थिति न केवल टीम की बल्लेबाजी को कमजोर करती है, बल्कि कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल और मुख्य कोच गंभीर को भी अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाध्य करती है।

विराट अपने नाम करेंगे खास रिकॉर्ड

कोहली ने द्विपक्षीय वनडे सीरीज के इतिहास में 196 पारियों में 9936 रन बनाए हैं। अगर कोहली इस मैच में 64 रन बना लेते हैं तो द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 10 हजार रन पूरे कर लेंगे और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिन्होंने 201 पारियों में 7669 रन बनाए हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे करने से सिर्फ 98 रन दूर रोहित

रोहित अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा के पास एक खास उपलब्धि को अपने नाम करने का मौका होगा। रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे करने से सिर्फ 98 रन दूर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सिर्फ 13 खिलाड़ी ही इस उपलब्धि को अपने नाम कर पाए हैं। 98 रन बनाते ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन बनाने वाले भारत के चौथे और दुनिया के 14वें क्रिकेटर बन जाएंगे। भारत के लिए यह कारनामा अभी तक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने ही हासिल किया है।

टीमें इस प्रकार

भारत : केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी

मलेशिया, नीदरलैंड ने की जीत से शुरुआत

एजेंसी ▶▶| मदुरै

मलेशिया और नीदरलैंड ने पूल ई के मैचों में क्रमशः ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड को हराकर एफआईएच पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की। मलेशिया ने दिन के पहले मैच में ऑस्ट्रिया को 5-1 से जबकि नीदरलैंड ने इंग्लैंड को 5-3 से हराया। मलेशिया के लिए दानिश खैरिल (56वें और 57वें मिनट) ने दो जबकि हैरिस उस्मान (28वें मिनट), एडम जोहरी (47वें मिनट) और नवीनेश पनिकर (55वें मिनट) ने एक-एक गोल किया। ऑस्ट्रिया का एकमात्र गोल 56वें मिनट में जूलियन कैसर ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया। इससे पहले नीदरलैंड की इंग्लैंड पर जीत में जान वैनट लैंड (दूसरे और 49वें मिनट) ने दो मैदानी गोल करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनके अलावा कैस्पर वैन डेर वीन (26वें मिनट) ने भी एक मैदानी गोल किया, जबकि जोप्पे वोलबर्ट (39वें मिनट) ने पेनल्टी स्ट्रोक पर और डैनिलो ट्राइलिंग (54वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके नीदरलैंड की जीत सुनिश्चित की। इंग्लैंड के लिए गोल कैडेन ड्रेसी (11वें), माइकल रॉयडेन (29वें) और जॉर्ज फ्लेचर

श्रीकांत, त्रीसा-गायत्री खिताब के करीब

लखनऊ। पूर्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत और गत चैंपियन त्रीसा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करते हुए सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्रमशः पुरुष एकल और महिला युगल फाइनल में जगह बनाई।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान

कोई योग्य मतदाता छूटे न, कोई अयोग्य मतदाता जुड़े न

1- अंदमान और निकोबार द्वीप
2- छत्तीसगढ़
3- गोवा
4- गुजरात
5- केरल
6- लक्षद्वीप
7- मध्य प्रदेश
8- पुडुचेरी
9- राजस्थान
10- तमिलनाडु
11- उत्तर प्रदेश
12- पश्चिम बंगाल

ECINet — A single unified mobile app for citizens
Integrates 40+ apps/websites related to voter services

पिछली SIR लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

Website के जरिए
- voters.eci.gov.in पर जाएँ
- "Search your name in last SIR" विकल्प को चुनें
- अपनी जानकारी भरें
  - राज्य चुनें
  - निर्वाचक का नाम दर्ज करें
  - Captcha भरकर Search पर क्लिक करें
- ज्यादा सटीक खोज के लिए रिश्तेदार का नाम चुनें; और अधिक सटीक खोज के लिए ज़िला/ विधानसभा क्षेत्र (AC) /भाग (Part) चुनें

ECINet APP के जरिए
- ECINet डाउनलोड करें और Voter Registration Forms पर क्लिक करें
- "Search your name in last SIR" विकल्प को चुनें
- अपनी जानकारी भरें
  - राज्य चुनें
  - निर्वाचक का नाम दर्ज करें
  - Captcha भरकर Search पर क्लिक करें
- ज्यादा सटीक खोज के लिए रिश्तेदार का नाम चुनें; और अधिक सटीक खोज के लिए ज़िला/ विधानसभा क्षेत्र (AC) /भाग (Part) चुनें

ऑनलाइन अपना गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरें

ECI वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, EPIC या ईमेल द्वारा OTP के माध्यम से लॉगिन करें
- SERVICES टैब में दिए Fill Your Enumeration Form पर क्लिक करें
- अपना राज्य चुनें, EPIC नंबर डालें और अपना Pre-Filled गणना प्रपत्र खोलें
- भारत से बाहर हैं तो Overseas Electors पर क्लिक करें और जानकारी भरें

ECINet APP
- APP Store पर जाएं
- ECINet APP डाउनलोड करें
- Voter Services टैब में जाएं और Voter Registration Form पर क्लिक करें

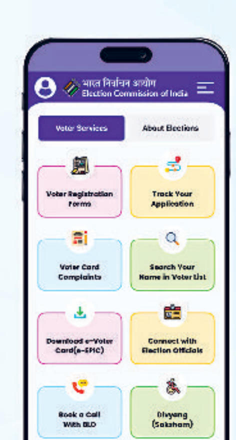

- Pre-Filled गणना प्रपत्र में अपनी जानकारी जांच लें
- अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से पूरा गणना प्रपत्र भरें
- गणना प्रपत्र में अपनी जानकारी जांचें, पिछली SIR लिस्ट से Linking करें, विवरण पूरा करें और फोटो अपलोड करें
- Preview में सभी जानकारी ध्यान से जांचकर Submit Enumeration Form पर क्लिक करें
- E-Sign करें और गणना प्रपत्र सफलतापूर्वक जमा करने की रसीद डाउनलोड करें

महत्वपूर्ण तारीख

गणना प्रपत्र भरने की अवधि:	4 नवंबर- 4 दिसंबर 2025
मतदाता सूची का प्रारुप (ड्राफ्ट) प्रकाशन:	9 दिसंबर 2025
दावे और आपत्तियों की अवधि:	9 दिसंबर 2025 - 8 जनवरी 2026
नोटिस फेज:	9 दिसंबर 2025 - 31 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन:	7 फरवरी 2026

Visit ECI Website
https://voters.eci.gov.in/

CBC 52101/13/0018/2526

fb.com/ECI | @ecisveep | youtube.com/eci | Election Commission of India | @ecisveep | Election Commission of India

खबर संक्षेप

गैंगस्टर बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की न्यायिक हिरासत को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यह निर्णय एनआईए मुख्यालय में एक विशेष सुनवाई के दौरान लिया गया। अनमोल बिश्नोई ने अदालत में एक आवेदन दायर कर अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। बता दें, अमेरिका से भारत आने पर एनआईए की टीम ने अनमोल को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। जहां से 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लौटने के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

ट्रंप का जी-20 में आमंत्रित नहीं करना अफसोसजनक

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि अमेरिका की अध्यक्षता के दौरान दक्षिण अफ्रीका को जी-20 में आमंत्रित नहीं किए जाने की उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा अफसोसजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में घोषणा की कि दक्षिण अफ्रीका को अगले वर्ष फ्लोरिडा में उनके देश की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका सदस्यता के लिए योग्य' नहीं है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर बोले

यूएस-चीन की नई वैश्विक शर्तों से दुनिया में अस्थिरता, सप्लाई चेन पर बढ़ता जा रहा है दबाव

चीन नवीकरणीय ऊर्जा पर हावी | यूएस बड़ा ऊर्जा निर्यातक बना

एजेंसी ⏭ कोलकाता

कोलकाता में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक राजनीति और आर्थिक समीकरणों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय ऐसे मोड़ पर है जहां अमेरिका और चीन की नई नीतियों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। बदलते हालात में देशों के सामने यह तय करना मुश्किल हो गया है कि उन्हें प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना चाहिए या उन समझौतों पर जो पीठ पीछे होते रहते हैं। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका अब पुराने ढांचे के तहत दुनिया का नेतृत्व नहीं कर रहा, बल्कि एक-एक देश के साथ सीधे और नई शर्तों पर बातचीत कर रहा है। दूसरी ओर, चीन भी अपने नियमों पर ज्यादा कठोरता से काम कर रहा है। इस स्थिति में दुनिया के कई देश असमंजस में हैं और संभावित जोखिमों से बचने के लिए सभी विकल्प खुले रख रहे हैं।

विश्व का एक तिहाई उत्पादन चीन में

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वैश्विकरण, सप्लाई असुरक्षा और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण देश हर आकस्मिकता के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जहां संभव हो, वे कठिन विकल्पों से बच रहे हैं और जहां फायदा दिख रहा है, वहां तुरंत निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की मांग और उत्साह में तेजी आई है। जयशंकर ने बताया कि वैश्विक उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा आज चीन में होता है, जिससे सप्लाई चेन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। संघर्षों और जलवायु संकटों ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। ऊर्जा के मामले में अमेरिका अब बड़ा निर्यातक बन गया है, जबकि चीन नवीकरणीय ऊर्जा पर हावी है।

व्यापार में मांग की अनिश्चितता बढ़ी

डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि व्यापार में मांग की अनिश्चितता और सप्लाई की बाधाएं जोखिम बढ़ा रही हैं। टैरिफ रेट्स में उतार-चढ़ाव से वैश्विक व्यापार पर अस्थिरता आई है। वित्तीय क्षेत्र में प्रतिबंधों का बढ़ता उपयोग, संपत्तियों की जब्ती और ब्लॉकचेन तकनीक का उभार नए वैश्विक वित्तीय ढांचे का संकेत दे रहे हैं। दुनिया एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर रही है जहां हर देश अपनी सुरक्षा, आर्थिक हितों और भविष्य की रणनीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। अमेरिका और चीन दोनों के साथ सीधे संवाद करते हुए देश समानांतर विकल्प भी तलाश रहे हैं ताकि किसी भी संकट में वे प्रभावित न हों।

ऊर्जा, व्यापार, और वैश्विक मसलों पर होगी चर्चा

पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले रूसी संसद का बड़ा फैसला

भारत और रूस के बीच सैन्य समझौते की पुष्टि, रक्षा संबंधों को होगा फायदा

◆ *पुराने भरोसेमंद संबंधों के नए दौर की शुरुआत*

एजेंसी ⏭ मॉस्को

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने दो दिन के भारत दौरे पर आएंगे। पुतिन राजकीय दौरे पर 4-5 दिसंबर को भारत आएंगे। इस यात्रा के दौरान पुतिन मुख्य रूप से 23वें भारत-रूस सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और भू-राजनीतिक मसलों पर अहम चर्चाएं होने की संभावना है।

इस दौरान व्लामीदर पुतिन की पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होगी। पुतिन के दिल्ली के इस अहम दौरे से पहले रूस की संसद (स्टेट डूमा) ने एक अहम सैन्य समझौते की पुष्टि का ऐलान किया है। रूस की संसद व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली आने से पहले भारत के साथ एक जरूरी मिलिट्री समझौते को मंजूरी देने जा रही है। दरअसल इस साल फरवरी में 2025 को भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (रेलोस-आरईएलओएस) हुआ था।

यह एग्रीमेंट स्ट्रेटेजि मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए है। पुतिन की भारत यात्रा और रेलोस समझौते को रूस की संसद द्वारा मंजूरी मिलना, दोनों देशों के बीच दशकों पुराने भरोसेमंद संबंधों के नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और वैश्विक समीकरणों के बीच यह दौरा भारत-रूस संबंधों को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फाइल फोटो

सैन्य सहयोग मजबूत होगा

यह महत्वपूर्ण सैन्य लॉजिस्टिक समझौता 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के तत्कालीन उप-रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन द्वारा साइन किया गया था। स्टेट डूमा ने रेलोस दस्तावेज को अपलोड किया है। इस समझौते का उद्देश्य है भारत और रूस की सेनाओं के बीच सामरिक गतिविधियों में लॉजिस्टिक सपोर्ट को आसान बनाना, संयुक्त सैन्य अभ्यासों को सुचारू करना, आपदा राहत अभियानों में तेजी लाना और सेना के अन्य ऑपरेशंस को सहयोगात्मक रूप से संचालित करना। रूसी सरकार का कहना है कि रेलोस समझौते की मंजूरी से दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में विश्वास और सहयोग नई मजबूती के साथ उभरेगा।

आपसी सैन्य गतिविधियां तेज हो जाएंगी

इस समझौते के लागू होने से भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य गतिविधियां काफी सरल और तेज हो जाएंगी। दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और नौसैनिक अड्डों का शांतिपूर्ण उद्देश्यों और सैन्य अभ्यासों के लिए उपयोग कर सकेंगे। आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने से सैनिकों, उपकरणों और सैन्य संसाधनों की तैनाती में समय और लागत दोनों कम होगी। यह समझौता भविष्य में आर्कटिक क्षेत्र में संभावित संयुक्त

भारतीय नौसेना रूसी नौसेनिक अड्डों का उपयोग कर सकेगी

भारतीय नौसेना के तलवार-श्रेणी के युद्धपोत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे बड़े जहाज रूस के उत्तरी समुद्री ठिकानों का उपयोग कर पाएंगे, जहां बर्फीले आर्कटिक का मौसम होता है। वहीं रूसी नौसेना भारतीय समुद्री ठिकानों और बंदरगाहों का उपयोग कर सकेगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह सहयोग भारत के लिए खास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर में चीन और अन्य बाहरी देशों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।

समझौता आर्कटिक क्षेत्र में भी लागू होगा

रेलोस समझौते का उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत और अन्य अभियानों के लिए समन्वय प्रक्रिया को आसान बनाना है। रेलोस से सैन्य अभ्यास और आपदा राहत अभियान समेत संयुक्त गतिविधियों के लिए प्रक्रियाएं सरल करके सैन्य सहयोग को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। इस प्रकार के समझौते सहभागी देशों के लिए शांतिकालीन अभियानों के भौगोलिक अवसरों का विस्तार करते हैं।

एलबीएसएनएए में बोले रक्षा मंत्री

ऑपरेशन सिंदूर नागरिक-सैन्य समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

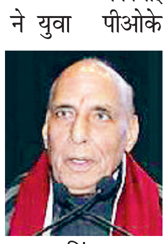

राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवा नागरिक सेवकों से राष्ट्रीय हितों की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने और वीर सैनिकों की तरह ही ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहने का आह्वान किया।

रक्षामंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नागरिक-सैन्य समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां प्रशासनिक मशीनरी ने सशस्त्र बलों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार किया और जनता का विश्वास जीता। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सशस्त्र बलों ने संतुलित और बिना किसी उकसावे के जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया।

लेकिन पड़ोसी देश के दुर्व्यवहार के कारण ही सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। उन्होंने सैनिकों की वीरता की सराहना की और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार किया और देश भर में मॉक ड्रिल का सफल संचालन सुनिश्चित किया। रक्षा मंत्री ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। इससे पहले, राजनाथ सिंह ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अकादमी परिसर में एक ओडीओपी मंडप का भी उद्घाटन किया।

इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन

279 की मौत, 174 लापता, कई क्षेत्रों में संपर्क कटा, मदद जारी

एजेंसी ⏭ अगम (इंडोनेशिया)

इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 279 हो गई है तथा अधिकारियों ने मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई है। उत्तरी सुमात्रा प्रांत में सड़कें खराब होने और संचार बाधित होने से इन इलाकों से संपर्क कट गया है और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए विमानों पर निर्भर रहना पड़ा। भारी उपकरणों की कमी के कारण बचाव कार्य भी बाधित हुए। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता फेरी वालिंटुकन ने बताया कि उत्तरी सुमात्रा में बचावकर्मियों ने शनिवार को 31 शव बरामद किए, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 279 हो गई। उन्होंने बताया कि 174 लापता लोगों की तलाश के लिए 3,500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है तथा प्रांत भर में अस्थायी सरकारी आश्रयों में शरण ले रखे 28,400 से अधिक लोगों को सहायता वितरित करने में मदद की जा रही है। सरकार की आपदा राहत एजेंसी के प्रमुख सुहार्यंतो ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोगों का पता नहीं चल पाया है। आचेह के गवर्नर मुज़ाकिर मनफ़ ने इस आपदा से निपटने के लिए 11 दिसंबर तक आपातकाल लगाये जाने की घोषणा करने के बाद कहा कि कई चुनौतियां हैं। हमें जल्द ही कई काम करने हैं, लेकिन हालात हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते।

दक्षिण सुमात्रा के बातंग तोरु में धंसी मस्जिद

स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट 'तारागिरी' नौसेना को सौंपा

मुंबई। नीलगिरि श्रेणी (प्रोजेक्ट 17ए) का चौथा और मझगांव डॉक शिपबिल्डिंग लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित तीसरा जहाज, तारागिरि (यार्ड 12653), 28 नवंबर 2025 को एमडीएल, मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इसमें शक्तिशाली हथियार और सेंसर सूट में ब्रह्मोस एसएसएम, एमएफएसटीएआर और एमआरएसएएम कॉम्प्लेक्स, 76 मिमी एसआरजीएम, और 30 मिमी और 12.7 मिमी निकटरक्षा हथियार प्रणालियों का संयोजन, साथ ही पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए रॉकेट और टॉरपीडो शामिल हैं।

म्यांमार नागरिकों ने भारतीयों के जीएसटी से कच्चा माल खरीदा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

क्रॉस-बॉर्डर नारकोटिक्स तस्करी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि म्यांमार मूल के लोगों ने भारतीय नागरिकों के जीएसटी प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग कर ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल खरीदा। यह खुलासा एजेंसी की उस कार्रवाई के दौरान सामने आया है, जब ड्रग्स तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में भारत-म्यांमार सीमा पर पहली बार तलाशी ली गई थी। ईडी ने 27 नवंबर को अपनी इस विशेष कार्रवाई के तहत मिजोरम के आइजोल और चंपाई (भारत-म्यांमार बॉर्डर) में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा असम के करीमगंज जिले के श्रीभूमि क्षेत्र और गुजरात के अहमदाबाद में भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूतों से पता चला है कि भारतीय नागरिकों ने म्यांमार के लोगों के लिए सूडोइफेड्रिन टैबलेट और कैफीन एन्हाइड्रस खरीदे। इन रसायनों का उपयोग सीमापार मेथामफेटामिन जैसी सिंथेटिक ड्रग्स के उत्पादन में किया जाता है।

इसी मकसद से यहां पिछले दिनों हुआ गौशाला का उद्घाटन

तिहाड़ के 'परेशान' कैदियों को मिल रही काऊ थैरेपी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली की तिहाड़ जेल में बुधवार को एक नई गौशाला का उद्घाटन किया गया। इस गौशाला का उद्देश्य न केवल देशी गायों, खासकर साहीवाल गायों का संरक्षण करना है बल्कि उन कैदियों को गौ-चिकित्सा (काऊ थैरेपी) भी प्रदान करना है जो परेशान हैं या जिनके रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आते।

उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने जेल में गौशाला का शुभारंभ किया। तिहाड़ के अधिकारियों ने बताया कि गौशाला में फिलहाल 10 गायें हैं जो कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और दयालुता के प्रसार में मदद करेगी। महानिदेशक (कारागार) एसबीके सिंह ने कहा, 'हमारे कुछ कैदियों से कोई मिलने या उन्हें फ़ोन करने नहीं आता। ऐसी पहल दूसरे देशों में भी की गई है।' तिहाड़ प्रशासन द्वारा रिसर्च के आधार पर काऊ थैरेपी से लाभ मिलने का दावा किया है।

हरियाणा में पहले से चल रही है यह थैरेपी

2018 में, हरियाणा की कुछ जेलों में गौ-चिकित्सा का एक नया रूप शुरू किया गया जहां कैदियों ने गौशाला में गायों की देखभाल का जिम्मा संभाला। तिहाड़ अधिकारियों के अनुसार, अच्छे आचरण के लिए जाने जाने वाले कैदी जेल में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। जेल ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जेल संख्या 2 और 3 में एक छोटी गौशाला के साथ इस पहल की शुरुआत की थी।

गौधन के संपर्क में आने से स्वास्थ्य में सुधार का किया गया है दावा

यह होते हैं लाभ

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार: गायों के साथ समय बिताने से कैदियों का तनाव और अकेलापन कम होता है। भावनात्मक तनाव से मुक्तिः यह थेरेपी कैदियों को भावनात्मक तनाव से उबरने और झगड़ों को कम करने में मदद कर सकती है। सकारात्मक आचरणः गायों की सेवा से कैदियों में ममता और वात्सल्य का भाव बढ़ता है, जिससे उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है।

यह है काऊ थैरेपी

तिहाड़ में 'काऊ थैरेपी' जेल में बनाई गई एक गौशाला है, जिसका उद्देश्य कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना है। यह उन कैदियों की मदद करती है जो अकेलापन और भावनात्मक तनाव महसूस करते हैं। इस पहल के तहत, कैदी गायों की देखभाल कर सकते हैं, जिससे उनमें दयालुता और वात्सल्य की भावना बढ़ती है। साथ ही, वे गायों से होने वाले उत्पादों (जैसे दूध, घी, छाछ) से आय भी कमा सकते हैं। यह पहल देशी गायों के संरक्षण में भी मदद करती है।

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक देवेन्द्र सिंह द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 से प्रकाशित। संपादक : डॉ. हिमांशु द्विवेदी। RNI No. 63924/1996, फोन : 9253681019-20, फैक्स : 274202, e-mail : rohtak@haribhoomi.com, rohtakharibhoomi@gmail.com
Postal Regd. No. P/RTK/389/2023-25